● वर्ष-2
● अंक-257
रायपुर, रविवार
18 जून 2023
● पृष्ठ-6
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

अवकाश सूचना

समाचार पचीसा के कार्यलय में 18 जून रविवार अवकाश रहेगा। समाचार पचीसा का अगला अंक 20 जून मंगलवार को प्रकाशित होगा।

कार से पहुंच सकेंगे बैंकॉक

भारत-म्यांमार-थाईलैंड को जोड़ने वाला त्रिपक्षीय राजमार्ग हो रहा तैयार

नई दिल्ली। थाईलैंड जैसे खूबसूरत देश में फ्लाइट के बजाय सड़क मार्ग के जरिए घूमने का सपना जल्द साकार हो सकता है। दरअसल, भारत-म्यांमार और थाईलैंड को जोड़ने वाला बहुप्रतीक्षित त्रिपक्षीय राजमार्ग अगले चार वर्षों में बनकर तैयार हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक, राजमार्ग के भारतीय और थाईलैंड भागों पर अधिकांश काम पूरा हो गया है।

1360 किलोमीटर लंबा भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग भारत, म्यांमार और थाईलैंड की एक साझी पहल है। भारत, म्यांमार में त्रिपक्षीय राजमार्ग के दो खंडों का निर्माण कर रहा है। इसमें 120.74 किलोमीटर कलेवा-याग्यी सड़क खंड का निर्माण और 149.70 किलोमीटर तामू-क्यिगोन-कलेवा (टीकेके) सड़क खंड पर अप्रोच रोड के साथ 69 पुलों का निर्माण शामिल है। नवंबर 2017 में टीकेके खंड के लिए और मई 2018 में कलेवा-यज्ञी खंड के लिए काम दिया गया था। उस वक्त दोनों परियोजनाओं को पूरा करने का निर्धारित समय काम शुरू होने की तारीख से तीन साल तय किया गया था। इन दोनों परियोजनाओं को म्यांमार सरकार को अनुदान सहायता के तहत भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है।

हाल ही में कोलकाता में बिम्सटेक देशों (बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड) का दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसी सम्मेलन में भाग लेने वाले म्यांमार

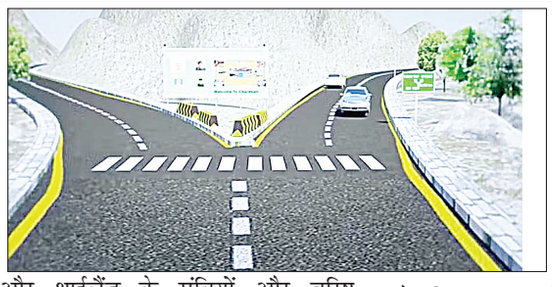

और थाईलैंड के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने जानकारी दी कि इस सड़क परियोजना पर काम अगले तीन से चार वर्षों के भीतर पूरा किया जाएगा। राजमार्ग के भारतीय और थाईलैंड भागों पर अधिकांश काम पूरा हो गया है, जबकि म्यांमार में असामान्य परिस्थितियों की वजह से निर्माण अभी रुका हुआ है।

म्यांमार के वाणिज्य मंत्री आंग नाइंग ओ की मानें तो म्यांमार के अंदर राजमार्ग का अधिकांश भाग पूरा हो चुका है। मंत्री ने 2026 के अंत तक अधूरे हिस्सों को पूरा करने के साथ-साथ अपग्रेडेशन वाले हिस्सों को पूरा करने के लिए उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि कलेवा और यार ग्यी के बीच राजमार्ग के 121.8 किलोमीटर के हिस्से को चार लेन के राजमार्ग में अपग्रेड किया जा रहा है और इसमें समय लग रहा है। थाईलैंड के विदेश मामलों के उप मंत्री विजावत इसराभकदी ने बताया कि थाईलैंड-म्यांमार सीमा पर स्थित बैंकाक से मॅई सॉट तक राजमार्ग का थाईलैंड भाग लगभग पूरा हो चुका है। यह 501 किलोमीटर का हिस्सा लगभग तैयार है। यह एशियाई राजमार्ग-1 का भी हिस्सा है। मंत्री ने कहा कि अभी कुछ हिस्सों में हाईवे के शोल्डर को पक्का करने और किनारे और डिवाइडर पर पेड़ लगाने और फूलों की झाड़ियां लगाने जैसे छोटे-मोटे काम चल रहे हैं। यह सब बहुत जल्द खत्म हो जाएगा।

किन-किन स्थानों को कवर करेगा राजमार्ग?

त्रिपक्षीय राजमार्ग कोलकाता में शुरू होता है, उत्तर में सिलीगुड़ी तक जाता है और यहां से यह पूर्व की ओर मुड़ता है। आगे कूचबिहार होते हुए बंगाल से बाहर निकलेगा और श्रीरामपुर सीमा के माध्यम से असम में प्रवेश करेगा। इस दौरान उत्तर बंगाल का दोआर्स क्षेत्र भी कवर होगा। यह दीमापुर से नगालैंड में प्रवेश करने के लिए असम में पूर्व दिशा के क्षेत्रों को कवर करता है। राजमार्ग फिर नगालैंड और मणिपुर के माध्यम से दक्षिण की ओर मुड़ता है। आगे इम्फाल से गुजरते हुए मोरेह के माध्यम से म्यांमार में प्रवेश करता है। मोरेह से, यह मॅई सॉट के माध्यम से थाईलैंड में प्रवेश करने के लिए मांडले, नैप्यीडॉ, बागो और म्यावाडी को पार करने के लिए दक्षिण-पश्चिम दिशा को कवर करता है।

2002 में आया था प्रस्ताव

त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना को पहली बार अप्रैल 2002 में म्यांमार में भारत, म्यांमार और थाईलैंड की एक मंत्रिस्तरीय बैठक में प्रस्तावित और अनुमोदित किया गया था। प्रस्ताव को उस समय अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा पेश किया गया था। वाजपेयी ने भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ (आसियान) के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए परियोजना का प्रस्ताव रखा था। वाजपेयी ने प्रस्ताव दिया था कि राजमार्ग को अंततः कंबोडिया के माध्यम से वियतनाम और फिर लाओस तक बढ़ाया जा सकता है। बाद में परियोजना केवल कागजों पर ही रह गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद इस पर काम शुरू हुआ।

भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना भारत की सबसे महत्वाकांक्षी लुक ईस्ट पॉलिसी का एक हिस्सा है। यह भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सबसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। इस परियोजना के पूरा होने के बाद, म्यांमार, थाईलैंड, हांगकांग और सिंगापुर सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र और अन्य एशियाई देशों के भीतर लोगों से लोगों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा।

10 राज्यों में सीबीआई का प्रवेश वर्जित

नई दिल्ली। विपक्ष शासित राज्यों में सीबीआई-ईडी जैसी सेंट्रल जांच एजेंसियों की एंट्री और एक्शन पर सवाल उठते रहे हैं। विपक्षी दलों की तरफ से ये आरोप भी लगाए जाते रहे हैं कि केंद्र सरकार के इशारे पर केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से विपक्षी दलों के नेताओं को निशाना बनाया जाता है। विपक्ष शासित 10 ऐसे राज्य हैं जहां सीबीआई बिना राज्य सरकार के इजाजत के कोई जांच या धर-पकड़ नहीं कर सकती है। तमिलनाडु इन 10 राज्यों की सूची में ताजा-ताजा जुड़ा है। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में जांच करने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को दी गई सहमति वापस ले ली।

तमिलनाडु सरकार ने लिया फैसला

राज्य के विद्युत और मद्यनिषेध एवं आबकारी मंत्री वी सेंथिल बालाजी को धनशोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किये जाने के दिन यह कदम उठाया गया है। गृह विभाग द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम,1946 (1946 का केंद्रीय अधिनियम 25) के एक विशेष प्रावधान के अनुसार सीबीआई को जांच करने के लिए जाने से पहले संबद्ध राज्य सरकार की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। इसमें कहा गया कि तमिलनाडु सरकार ने उक्त नियम के तहत 1989 और 1992 में कुछ तरह के मामलों में दी गई सहमति वापस लेने का आदेश जारी किया। इस तरह, सीबीआई को राज्य में जांच करने के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी।

सीबीआई जांच

अगर कोई राज्य सरकार किसी आपराधिक मामले की जांच का सीबीआई से आग्रह करती है तो सीबीआई को पहले केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी किया जाता है। जिसके बाद सीबीआई द्वारा तफ्तीश शुरू की जाती है। वहीं भारत का सुप्रीम कोर्ट या राज्यों के हाई कोर्ट भी मामले की जांच का सीबीआई को आदेश दे सकते हैं।

इन राज्यों में सीबीआई की एंट्री बैन

विपक्षी शासित राज्यों- पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल, मेघालय, तेलंगाना और मिजोरम के बाद अब तमिलनाडु भी केंद्रीय जांच एजेंसियों पर बैन लगाने वाले राज्यों में शुमार हैं। मेघालय ऐसा करने वाली पहली एनडीए सरकार बनी। इन राज्यों ने सीबीआई को जांच के लिए दी जाने वाली %सामान्य सहमति% को हटा दिया। इन राज्यों में अगर किसी मामले की जांच सीबीआई को करनी है, तो राज्य सरकार से पूछना होगा। जिन राज्यों में %सामान्य सहमति% नहीं दी गई है या फिर जहां विशेष मामलों में सामान्य सहमति नहीं है, वहां डीएसपीई एक्ट की धारा 6 के तहत राज्य सरकार की विशेष सहमति जरूरी है।

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेशव्यापी भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में प्रदेश की विधानसभाओं में पहुंचकर वहां लोगों से प्रत्यक्ष मुलाकात की थी और शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी स्थिति जानी थी। इस दौरान उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के ही ग्रामीण परिवारों के साथ उनका पारंपरिक भोजन किया था। ग्रामीण परिवारों ने भी अपने घर में मुख्यमंत्री का पारंपारिक तरीके से स्वागत किया और भोजन के दौरान मुख्यमंत्री से घर परिवार की बात की थी।

सामान चोरी हुआ तो रेलवे नहीं होगा जिम्मेदार

नई दिल्ली। ट्रेन में सफर के दौरान अगर आपका सामान चोरी हो जाता है, तो इसके लिए अब भारतीय रेलवे जिम्मेदार नहीं होगा। यात्रियों को अपने सामान की सुरक्षा खुद करनी होगी। रेल यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कहा कि ट्रेन में यात्रा करते समय अगर किसी यात्री का सामान चोरी हो जाता है, तो इसके लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इसे रेलवे की सेवाओं में कमी के तौर पर नहीं माना जा सकता है। रेलवे का काम ट्रेन सेवा मुहैया कराना है। यात्रा के दौरान सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल सवारी की है।

दरअसल, कोर्ट ने यह फैसला कपड़ा व्यापारी सुरेंद्र बोला की याचिका के जवाब में दिया है। 27 अप्रैल 2005 को सुरेंद्र काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस की रिजर्व सीट

पर बैठकर नई दिल्ली जा रहे थे। इस दौरान एक लाख रुपये की राशि उनके पास थी। लेकिन 28 अप्रैल को तड़के साढ़े तीन बजे जब सुरेंद्र उठे, तो उनके पैसे चोरी हो चुके थे। इसके बाद दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने जीआरपी थाने उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई।

यहीं नहीं इसके कुछ दिन बाद उन्होंने शाहजहांपुर के जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई। जिला उपभोक्ता फोरम में बहस के दौरान सुरेंद्र ने रेलवे की सेवा में कमी की बात कहते हुए हर्जाना दिए जाने की मांग की। जिला उपभोक्ता फोरम ने सुरेंद्र के पक्ष में फैसला सुनाया। रेलवे को एक लाख रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया गया। इसके बाद भारतीय रेलवे ने जिला उपभोक्ता अदालत के इस फैसले को रेलवे ने ऊपरी अदालत में चुनौती दी। लेकिन राज्य और राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम की तरफ से फिर रेलवे को झटका लगा। दोनों ने जिला फोरम के फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिल विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की डबल बेंच ने यात्री के पक्ष में दिए गए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के आदेश को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यात्री के निजी सामान का रेलवे द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से कोई लेना देना नहीं है। यह हमारी समझ से परे है कि कैसे चोरी को किसी भी संदर्भ में रेलवे द्वारा दी जा रही सेवाओं में कमी के तौर पर देखा जा सकता है। जब सवारी खुद अपने निजी सामान की रक्षा नहीं कर पाई तो इसके लिए रेलवे को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश देते हुए जिला, राज्य और राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम के फैसले को रद्द कर दिया। रेलवे की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, चलती ट्रेन से अगर किसी यात्री का सामान चोरी होने या लूट हो जाने पर वह रेलवे कंडक्टर, कोच अटेंडेंट, गार्ड या जीआरपी एस्कॉर्ट से संपर्क कर सकता है। यहां आपको शिकायत दर्ज कराने के लिए सहायता की जाएगी।

प्रमुख समाचार

भारतीय दूतावास पर हमलों की जांच एनआईए ने संभाली

नई दिल्ली। अमेरिका और कनाडा के भारतीय दूतावास में हुए हमलों की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी करेगी। मार्च में खालिस्तान समर्थकों ने दोनों देशों के भारतीय मिशनों पर हमले किए थे। इसके अलावा, इंग्लैंड स्थित भारतीय उच्चायोग में हुए हिंसक प्रदर्शन और तोड़फोड़ के प्रयास किए गए थे, जिसकी जांच भी एनआईए कर रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मार्च में हुए हमलों के संबंध में गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की थी। खालिस्तान समर्थकों ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय मिशनों पर हमला किया था। उन्होंने वहां खालिस्तान समर्थक नारे भी लगाए थे। प्रदर्शनकारियों ने शहर में लगाए गए अस्थाई सुरक्षा अवरोधकों को भी तोड़ दिया था। प्रदर्शनकारियों ने दूतावास के अंदर दो खालिस्तानी झंडे भी लगाए थे। हालांकि, बाद में उसे हटा दिया गया था। भारत ने घटना का कड़ा विरोध किया था। इसके अलावा भारत ने कनाडा के भारतीय राजदूतों पर हुए हमलों के बारे में भी जानकारी मांगी थी।

स्टालिन तानाशाह की तरह व्यवहार कर रहे हैं- चंद्रशेखर

पणजी। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शनिवार को कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन पूर्व सोवियत तानाशाह जोसेफ स्टालिन

की तरह काम कर रहे हैं, जिनके लिए लोगों की स्वतंत्रता और उनके अधिकार मायने नहीं रखते थे। वह एक कथित सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत भाजपा की तमिलनाडु इकाई के नेता एस. जी. सूर्या की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। पुलिस सूत्रों ने कहा कि यह कार्रवाई भाजपा के प्रदेश सचिव सूर्या द्वारा उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी एक पोस्ट को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से की गई शिकायत के आधार पर की गई। चंद्रशेखर ने दक्षिण गोवा के मडगांव शहर में 'पीटीआई-भाषा' से कहा, ''कल, तमिलनाडु से हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया।

शरद पवार को था एनडीए में शामिल होने का प्रस्ताव-प्रफुल्ल

नईदिल्ली। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद प्रफुल्ल पटेल ने शनिवार को दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी

वाजपेयी के एक प्रस्ताव को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया। पटेल ने खुलासा किया कि वाजपेयी ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को केंद्र सरकार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल होने का मौका दिया था। 1999 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से शरद पवार के विभाजन के बारे में पटेल की चर्चा के दौरान रहस्य से पर्दा हटा। मीडिया रिपोर्ट की माने तो पटेल ने कहा कि एनसीपी के कांग्रेस से अलग होने के बाद, वाजपेयी ने महाराष्ट्र में शिवसेना-भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ गठबंधन करने के लिए पवार को निमंत्रण दिया था। हालाँकि, पटेल ने स्वीकार किया कि सबसे बड़ी पार्टी बनने की उनकी आकांक्षाओं के बावजूद, उस समय परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थीं।

मणिपुर हिंसा पर पीएम मोदी 40 दिन बाद भी चुप- जयराम

नईदिल्ली। कांग्रेस महासचिव प्रभारी संचार जयराम रमेश ने कहा कि 10 जून से मणिपुर की 10 विपक्षी पार्टियां प्रधानमंत्री से मिलने के मौके

का इंतजार कर रही हैं... उन्होंने 10 जून को पीएम को पत्र भेजा और उनसे मिलने का अनुरोध किया, वे अभी भी इंतजार कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि 20 जून को विदेश यात्रा पर जाने से पहले प्रधानमंत्री उनसे मिलने का समय निकाल लेंगे। मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मेघचंद्र सिंह ने कहा कि मणिपुर राज्य में हिंसा रुकने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं हैं, और कोई इंटरनेट नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप व्यापक पीड़ा हो रही है। हम, समान विचारधारा वाले 10 राजनीतिक दलों के नेता, पीएम मोदी से मिलने का समय लेने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं, क्योंकि वह मणिपुर के मुद्दों के बारे में बेफिक्र दिखाई देते हैं।

रथ यात्रा उत्सव के दौरान 25 लाख लोगों के आने की उम्मीद

पुरी। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन को विश्व प्रसिद्ध पुरी रथ यात्रा उत्सव के दौरान इस बार करीब 25 लाख

लोगों के आने की उम्मीद है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। रथ यात्रा महोत्सव 20 जून से शुरू होगा। यह बात श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (एसजेटीए) के मुख्य प्रशासक रंजन कुमार दास ने कही। एसजेटीए के मुख्य प्रशासक रंजन कुमार दास ने पीटीआई-से कहा कि इस महापर्व को सुचारू रूप से संपन्न कराने को लेकर प्रशासन पूरी तरह से आशान्वित है। उन्होंने कहा, हम 20 जून को श्री गुंडिचा दिवस के अवसर पर पुरी में लगभग 10 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद कर रहे हैं, इस दौरान भक्तों द्वारा रथ खींचे जाएंगे। उन्होंने बताया कि रथ यात्रा उत्सव में बहुदा (रथ वापसी उत्सव), सुना भेसा (देवताओं की सुनहरी पोशाक) और नीलाद्री बिजे (मुख्य मंदिर में वापसी) भी शामिल हैं।

कांग्रेस से कुर्बानी की उम्मीद के कारण विपक्ष में एकता हो पाना मुश्किल

योगेंद्र योगी

विपक्षी दल आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस की कुर्बानी चाहते हैं। कांग्रेस इस एकता के पीछे छिपे विपक्षी दलों के अपने राज्यों में अकेला रहने की नीयत को अच्छी तरह पहचानती है। इस एकता की कवायद को लेकर विपक्षी दलों की हालत इधर कुआ और उधर खाई जैसी हो गई है। विपक्षी दलों को भाजपा के साथ ही कांग्रेस से भी खतरा है। भाजपा से मुकाबले में वोटों के बिखराव को रोकने के लिए विपक्षी दल कांग्रेस को भी अपने जनाधार वाले राज्यों से चुनावी मैदान से हटाने चाहते हैं। ऐसे में विपक्षी एकता के लिए 23 जून को नीतिश कुमार के आह्वान पर पटना में होने वाली बैठक में एकराय कायम करने का मामला खटाई में पड़ता नजर आ रहा है।

गौरतलब है कि हिमाचल और कर्नाटक का चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस के मंसूबे सातवे आसमान पर हैं। कांग्रेस को भी अंदाजा है कि है कि भाजपा के साथ-साथ विपक्षी दलों के प्रभाव वाले राज्यों में चुनाव लड़े बगैर केंद्र में सरकार बनाने और राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा नहीं हो सकता। कांग्रेस ने बेशक अपनी महत्वाकांक्षा का खुलकर इजहार नहीं किया है, किन्तु उसके इरादो से साफ जाहिर है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। विपक्षी दल चाहते हैं कि कांग्रेस सिर्फ उन्हीं 200 संसदीय सीटों पर फोकस करना चाहिए, जहां बीजेपी से उसका सीधा मुकाबला है। विपक्ष की शर्तों पर कांग्रेस राजी नहीं है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हो रही विपक्षी एकता के मसले पर

जो बात ममता कह रही हैं वही अखिलेश और केसीआर भी कह रहे हैं कि जहां पर जो दल मजबूत है, वो चुनाव लड़े और विपक्ष के बाकी दल उसे समर्थन करें। लेकिन कांग्रेस इस पर रजामंद नहीं है। कांग्रेस को पता है कि इन जहां भाजपा से सीधा मुकाबला है, वहां तीसरा मजबूत दल नहीं है। इसलिए विपक्ष की यह खैरात कांग्रेस को पसंद नहीं है। इन सीटों पर अन्य दल चाह कर भी कांग्रेस और भाजपा के बीच आकर मुकाबले त्रिकोणीय या बहुल नहीं बना सकते, ऐसे में कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के आधार वाले राज्यों में चुनाव नहीं लडने की शर्त को कभी स्वीकार नहीं करेगी।

कांग्रेस उन 200 लोकसभा सीटों पर तो चुनाव लडना चाहती है, जिस पर उसे सीधे बीजेपी से लडना है। इसके साथ-साथ कांग्रेस की नजर उन राज्यों की सीटों पर भी है, जहां भाजपा के मुकाबले क्षेत्रीय दल मजबूत हैं। लेकिन क्षत्रप अपने राज्यों में कांग्रेस को स्थान नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उनका सियासी आधार कांग्रेस की जमीन पर खड़ा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत तमाम विपक्षी दल के नेता चाहते हैं कि कांग्रेस उनके प्रभाव वाले राज्यों से चुनाव नहीं लड़े, ताकि भाजपा से सीधे मुकाबले में वोटों का बंटवारा नहीं हो। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि हमने अनुमान लगाया है कि कांग्रेस 200 सीटों पर मजबूत है। अगर कांग्रेस कुछ अच्छा चाहती हैं तो कुछ जगहों पर त्याग भी करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश (सपा) को प्राथमिकता देनी होगी। ममता ने दूसरे राज्यों का भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि बंगाल, दिल्ली, तमिलनाडु, झारखंड, पंजाब, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा में जनता के बीच मजबूत पकड़ रखने वाली पार्टियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। बिहार में नीतीश, तेजस्वी और कांग्रेस साथ हैं तो वे फैसला ले सकते हैं।

विपक्षी दलों को लगता है कि कांग्रेस उनके प्रदेश में अगर मजबूत होती है, तो भविष्य में उनके लिए ही चिंता बढ़ा सकती है। इसीलिए विपक्षी दल कांग्रेस को उन्हीं सीटों के इर्द-गिर्द रखना चाहतें हैं, जहां उसका मुकाबला सीधा भाजपा से है। कांग्रेस इस बात को समझती है कि केंद्र की सत्ता को दोबारा से हासिल करनी है तो उसे पहले राज्यों में मजबूत होना होगा, इसीलिए कांग्रेस विपक्षी एकता से ज्यादा फोकस राज्यों के चुनाव पर कर रही है ताकि पहले खुद मजबूत हो ले। कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव नतीजों के वोटिंग ट्रेंड का आंकलन करते हैं तो राज्य की 29 लोकसभा सीटों में से सिर्फ बीजेपी को 4 सीटों पर बढ़त मिली है जबकि 21 सीटों पर कांग्रेस आगे रही है। इन राज्यों के चुनाव नतीजों को 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जाएगा।

नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार बस्तर फाइटर्स, जंगलवार कॉलेज में ट्रेनिंग हुई पूरी

कांकेर। जंगलवार कॉलेज कांकेर में बस्तर फाइटर्स की 47 दिन की एडवांस ट्रेनिंग शुक्रवार को खत्म हो गई है। अंतिम दिन बस्तर फाइटर्स को ब्लास्ट और बंदूक के बीच ट्रेनिंग दी गई। जिसके बाद ये फाइटर्स मैदान-ए-जंग में नक्सलियों से लोहा लेने के लिए तैयार हैं। जंगलवार के ट्रेनरों द्वारा फायरिंग करने के साथ कई आईडी में ब्लास्ट भी किया गया। डेमो के दौरान बस्तर फाइटर के दो प्रशिक्षु जवान घायल हो गए। घटना के तत्काल बाद कुछ देर के लिए डेमो रोका और दोनों जवानों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद दोबारा डेमो शुरू हुआ लेकिन आईडी ब्लास्ट नहीं किया गया।

बस्तर से चुने गए 640 बस्तर फाइटरों को पुलिस की बेसिक ट्रेनिंग देने के बाद नक्सलियों के खिलाफ गुरिल्लावार पैर्टन से लड़ाई लड़ने 47 दिन की एडवांस ट्रेनिंग के लिए जंगलवार कॉलेज भेजा गया था। इससे पहले जगदलपुर व अन्य स्थानों में उन्हें पुलिस की बेसिक ट्रेनिंग दी गई थी। दो मई से शुरू हुई इस ट्रेनिंग में बस्तर फाईटर को फायरिंग, रेड, आरओपी, पेट्रोलिंग, एंबुश, एमसीपी, बम से बचने, सिविक एक्शन की विशेष ट्रेनिंग दी गई। 16 जून को ट्रेनिंग खत्म होने के बाद इन्हें मैदान-ए-

जंग में भेजने से पहले बम ब्लास्ट व बंदूक की गोलियों की गूंज की दशहत खत्म करने के लिए डेमो दिया गया। सौ-सौ की संख्या में जंगलवार कॉलेज के फायरिंग रेंज स्थित सूखे तालाब में नीचे उतरे तथा उनके 15 फीट उपर से ट्रेनरों ने एलएमजी से गोलियां चलानी शुरू की।

डेमो के दौरान विस्फोट के लिए आईडी जंगलवार कॉलेज में ही एक्सपर्ट ट्रेनरों ने तैयार की थी। इसमें मात्र दो सौ ग्राम ही बारूद भरा गया था। डेटोनेटर लगा कर उसमें विस्फोट करने बैटरी से कनेक्ट किया गया था। आईडी में सुरक्षा को देखते लोहे के टुकड़े, छर्रे या स्प्रिंटर आदि नहीं भरे गए थे। ब्लास्ट होने के बाद उसके आसपास से उड़ने वाली गिट्टी ने जवानों को गंभीर रूप से घायल कर दिया।

42 डिग्री तापमान में दी ट्रेनिंग

इस साल भीषण गर्मी पड़ रही है। 42 डिग्री तापमान वाली गर्मी में जहां दोपहर में घर से निकलना मुश्किल है वहां बस्तर फाइटर्स ने जंगलवार कॉलेज में कड़ी मशक्कत करते हुए ट्रेनिंग ली। ट्रेनरों का भी कहना है इतनी गर्मी में अबतक किसी ने ट्रेनिंग नहीं ली है। फिर भी बस्तर फाइटर्स के जवानों ने पूरी शिद्दत के साथ ट्रेनिंग ली है। इनमें काफी सहनशीलता है जो साबित कर रहा है कि यह अबतक का सबसे अच्छा बैच है।

डायरेक्टर जंगलवार कॉलेज बिग्रेडियर स्वर्ण कुमार लामा ने कहा बस्तर फाइटर्स कमांडो ट्रेनिंग के लिए कॉलेज में आए थे। मैंने इन्हें करीब से देखा है ये बड़े जांबाज हैं। अब तक यहां जितने भी जवान आए उनसे कहीं ज्यादा इनमें काबिलियत है। इन्हें युद्ध की ट्रेनिंग दी गई है। इनके उपर से गोलियां निकलती थी और बगल में ब्लास्ट होता है। अब वे परिपक्व हो चुके हैं। पूरे जोश के साथ आज डेमो दिया। ट्रेनिंग में चोट लगना आम बात है। आज दो जवान घायल हुए हैं लेकिन उनके हौसलें बुलंद हैं।

बुनियादी सुविधाओं पर महापौर परिषद ने लगाई मुहर

दुर्ग। नगर पालिक निगम के डाटा सेंटर हॉल में मेयर इन काउंसिल की बैठक महापौर धीरज बाकलीवाल के अध्यक्षता एमआईसी व निगम अफ़्सरो की मौजूदगी में विकास कार्यों सहित अन्य विषयों को लेकर आयोजित की गई। बैठक में मौजूद एमआईसी के सभी सदस्य एवम् उपायुक्त मोहेंद्र साहू,कार्यपालन अभियंता राजेश पांडेय, प्रकाशचंद थवानी,जितेंद्र समैया,गिरीश दिवान,राजकमल बोरकर,थानसिंग यादव आदि मौजूद थे। बैठक में 11 एजेंडों पर चर्चा की गई। जिंसमे लोक कर्म विभाग,जलकार्य विभाग और स्वास्थ्य विभाग पर विशेष रूप से चर्चा कर एजेंडों को स्वीकृति दी गई। पार्षद प्रेमलता साहू द्वारा बोरसी वार्ड में स्थित प्रगति मैदान में मां कर्मा उद्यान एवं मानवता स्कूल के पास स्थित गार्डन को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क के रूप में नामकरण हेतु पत्र प्रस्तुत की जिसे स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा नगरीय प्रशासन विकास विभाग के प्रबोधन/गौरव समागम कार्यक्रम 2023 अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा नगर निगम दुर्ग हेतु राशि रू. 25 करोड़ के कार्यों की घोषणा की गई हैं। जिसके तहत् नगर निगम दुर्ग क्षेत्रांतर्गत विभिन्न

वार्डो में आधुनिक शौचालयों के निर्माण हेतु आबादी के अनुपात में आवश्यकतानुसार राशि रू. 90 लाख का प्रस्ताव तैयार किया गया हैं। प्राप्त निर्देशानुसार आगामी महापौर परिषद की बैठक में स्वीकृति की प्रत्याशा में प्रस्ताव शासन की ओर प्रेषित किया गया है जिसे स्वीकृति मिली।नगरीय प्रशासन विकास विभाग के प्रबोधन / गौरव समागम कार्यक्रम 2023 अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा नगर निगम दुर्ग हेतु राशि रू. 25 करोड़ के कार्यों की घोषणा की गई है। जिसके तहत रीपा की तर्ज पर शहरों में अर्बन काटेज एंड सर्विस इंडस्ट्रीज पार्क लगाये जाने हेतु नगर पालिक निगम दुर्ग क्षेत्रांतर्गत उक्त कार्य हेतु राशि रू. 2 करोड़ की घोषणा अनुसार प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्राप्त निर्देशानुसार आगामी महापौर परिषद की बैठक में स्वीकृति की प्रत्याशा में प्रस्ताव शासन की ओर प्रेषित किया गया है। विभाग द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। लोक कर्म विभाग द्वारा राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना महात्मा गांधी अर्बन इन्डस्ट्रीयल पार्क (ङ्क्क) का निर्माण वार्ड कं0-35 पुलगाव के गोकुल नगर गौठान के समीप किया जा रहा है, जिसमें लगभग 4.37 एकड़ जमीन पर नये युवा उद्यमीयों तथा स्वङ्क्सहायता समूहों को भूखण्ड उपलब्ध करा कर लघु एवं कुटीर उद्योग स्थापित किये जाने हेतु प्रेरित किया जायेगा। उक्त योजना में चिन्हांकित भूमि पर मूलभूत सुविधाओं जैसे-सड़क, नाली, बिजली, पानी, सुलभ एवं अन्य कार्यों के साथ-साथ मशीन कय करने व योजना के प्रचार-प्रसार हेतु लागत राशि 200.00 लाख रूपये का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) तैयार किया गया है जिसके अनुमोदन हेतु विभाग द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। साथ ही गंजपारा चौक से शिवनाथ नदी मार्ग चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु 14वे वित्त आयोग संचालनालय पत्र द्वारा रूपये 484.77 लाख की स्वीकृत प्राप्त हैं।

हत्या का प्रकरण दर्ज कराने पूर्व विधायक व भाजपा पदाधिकारी पहुंचे खड़गवां थाना

चिरमिरी/खड़गवां। मनेन्द्रगढ़ विधायक के भाई विनोद जायसवाल के क्रेसर में गत दिनों हुई मौत के मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज कराने खड़गवां थाना पूर्व विधायक व भाजपा पदाधिकारी पहुंचे।

खड़गवां थाना पहुंचे पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल एवं भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि विगत 04 जून 2023 को विधायक विनय जायसवाल के भाई विनोद जायसवाल के क्रेसर जो कि खड़गवां बिजली आफिस के सामने संचालित है। जिसमें आपरेटर के रूप में कार्यरत आनंद उर्फ राजू गोंड पिता स्व. देवी सिंह निवासी नागपानी ग्राम पंचायत आमाडांड की मृत्यु संदिग्ध परिस्थिति में हो गई थी। इससे साफ जाहिर है क्रेसर संचालक की लापरवाही के कारण ही आपरेटर की मृत्यु हुई है। जिसके बाद आनन फानन में मृतक के शव को खड़गवां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजा गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया था। सुबह होते ही मृतक का पोस्टमार्टम कर दिया गया और पुलिस ने भी केवल मर्ग कायम कर अपनी खाना पूर्ति कर ली थी। इससे साफ जाहिर होता है कि क्षेत्रीय विधायक के दबाव में कहीं न कहीं आज घटना को 10 दिन से भी ज्यादा बीत जाने के बाद भी पुलिस ने किसी भी प्रकार की जांच न करते हुए मामले को ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास किया है। अपराधियों को बचाने का जो कार्य किया है उसके खिलाफ हम थाने में आज मृतक के परिजनों को इंसाफ दिलाने के लिए उपस्थित हुये है। हमारी मांग है कि आगामी 7 दिवस के भीतर यदि क्रेसर संचालन विधायक के भाई विनोद जायसवाल के उपर मामला पंजीबद्ध नहीं किया जाता है, तो भाजपा खड़गवां मंडल थाना का घेराव करते हुए उग्र प्रदर्शन करने का बाध्य होगी।

इस दौरान भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेणुका सिंह, जनपद अध्यक्ष श्रीमती सोनमती उर्रे, जिला मंत्री अरूणोदय पाण्डेय, मंडल अध्यक्ष रामलाल साहू, चिरमिरी मंडल अध्यक्ष रघुनंदन यादव, भाजयुमो मंडल अध्यक्ष रामप्रताप, पूर्व मंडल अध्यक्ष धनंजय पाण्डेय, द्वारिका जायसवाल, लखन लाल श्रीवास्तव, हेन्द्रपाल सिंह उपस्थित रहे।

विधानसभा स्तरीय भाजपा का सम्मेलन खड़गवां में

एमसीबी। भारतीय जनता पार्टी मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर मे महा जनसंपर्क अभियान के तहत मनेन्द्रगढ़ विधानसभा स्तरीय लाभार्थी सम्मलेन कार्यक्रम के लोकसभा सयोंजक श्रीमती चम्पा देवी पावले एवं सह संयोजक जोगेष लम्बा के मुख्य अतिथ्य, तथा भाजपा जिला प्रभारी श्रीमति उदेश्वरी पैकरा, भाजपा जिलाध्यक्ष माननीय अनिल केसरवानी, की अध्यक्षता में लाभार्थी सम्मेलन जिला प्रभारी लखन श्रीवास्तव एवं सह प्रभारी अभय जयसवाल मनेन्द्रगढ़ विधानसभा प्रभारी मनोज शर्मा एवं भाजपा के अन्य पदाधिकारी एवं वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में कार्यक्रम किया जाना सुनिश्चित किया गया है जो निम्नानुसार तो जो दिनाक 17/06/2023 को दोपहर 02:00 बजे दिन- शनिवार को खडगवां सामुदायिक भवन में सम्पन्न होना सुनिश्चित हुआ है तथा उक्त कार्यक्रम मे मनेन्द्रगढ़ विधान सभा में निवासरत सभी मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी, जिला एवं मंडल पदाधिकारी, कार्यसमिति सदस्य व

वरिष्ठ भाजपा नेता, पार्षद/जिला सदस्य/जनपद सदस्य/सरपंच/पंच/ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्त्ता आमंत्रित है! जिसमें पदाधिकारी एवं समस्त कार्यकर्त्ता गणों सदस्यों से आग्रह है कि अपने साथ न्यूनतम 5-5 लाभार्थियों के साथ समय पर कार्यक्रम सम्मेलन स्थल मे उपस्थित होने का आग्रह किया गया है, तथा मंडल मे निवासरत सभी शक्ति केंद्र प्रभारी/संयोजक/सह संयोजक से विशेष रूप से आग्रह है कि आपके प्रभार क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड/पंचायत व बूथ से केंद्र सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं के लाभार्थियों को सूचित कर अपने साथ लेकर आने का अनुरोध किया गया है।

विधायक के प्रयासों से शहर के सौंदर्यीकरण को लगा चार चांद

बेमेतरा। विधायक आशीष छाबड़ा के प्रयासों से नगर पालिका परिषद बेमेतरा को राज्य शासन से पूर्व में आठ चौक चौराहों के निर्माण हेतु राशि प्राप्त हुई थी इस बार राज्य शासन ने और 7 नवीन चौक निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है जिसमें नाई समाज के प्रतीक स्वरूप से श्री सेन चौक के निर्माण हेतु 18 लाख की राशि श्री झूलेलाल चौक निर्माण हेतु 20 लाख राशि स्वीकृत शहीद वीर नारायण चौक आदिवासी समाज 15 लाख रुपए संत श्री गाडगे चौक धोबी समाज 15 लाख रुपए निषाद समाज चौक 15 लाख रुपए पृथ्वीराज चौहान चौक 15 लाख रुपए नामदेव चौक 15 लाख रुपए राज्य शासन ने स्वीकृत किए हैं।

ज्ञात हो कि इन चौकों के निर्माण पश्चात बेमेतरा शहर के सौंदर्यीकरण को एक नया स्वरूप प्राप्त हो सकेगा साथ ही विभिन्न समाजों के प्रतिनिधित्व स्वरूप समाज के पूज्यनीय के नाम स्वरूप चौक का निर्माण किया जा सकेगा इससे ना केवल आने वाले पीढ़ी को समाज के उद्धारकओं के बारे

में प्रेरणा मिल सकेगी बल्कि भारत के विविधता में एकता को भी बल मिल सकेगा ज्ञात हो कि इन चौक चौराहों के निर्माण हेतु विधायक आशीष छाबड़ा सहित नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती शकुंतला मंगल साहू लगातार प्रयासरत थे जिसका नतीजा है कि बेमेतरा शहर को इन चौक निर्माण की स्वीकृति मिल सके पूर्व में बनाए गए चौक निर्माण से बेमेतरा शहर अब देखते ही बनता है इससे पूर्व किसी जनप्रतिनिधि ने अब तक बेमेतरा शहर को सजाने के बारे में नहीं सोचा था जब से बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा बने हैं तब से उन्होंने पूरे विधानसभा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को लेकर मानो एक जंग छेड़ दिया हो जिसका नतीजा है कि बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र से चहूं और विकास की ओर गतिमान है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

धर्मांतरण कराने पहुंची महिला व युवती की जमकर पिटाई

दुर्ग। मोहन नगर थाना क्षेत्र के उरला बस्ती में धर्मांतरण कराने लोगों को उकसा रही एक महिला व एक युवती की आक्रोशित भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी। मामला थाना तक पहुंचा जहां दोनों पक्षों के मध्य समझौता हो गया। सूत्रों ने बताया कि घटना 3-4 दिन पूर्व का है। उरला बस्ती में एक महिला के घर पर प्रार्थना सभा आयोजित थी। बताया जाता है कि प्रार्थना कराने के लिए बाहर से एक महिला व एक युवती वहां पहुंची हुई थी। बताया जाता है कि महिला और युवती उपस्थित लोगों से धर्म परिवर्तन करने तथा प्रभु की कृपा होने का झांसा देकर ईसाई धर्म अपनाने उकसा रही थी। इस बात की जानकारी मोहल्ले के लोगों को हुई तो उन्होंने इसका विरोध किया। इस बीच जिस घर में यह प्रार्थना सभा हो रही थी, उस घर की प्रमुख महिला वहां से निकल गई। आक्रोशित भीड़ ने प्रार्थना कराने पहुंची महिला व युवती को पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई की। इसके बाद उन्हें थाना लाया गया, जहां दोनों पक्षों के बीच समझौता होने की बात सामने आई है।

बीएड में एडमिशन के लिए प्री बीएड पास करना अनिवार्य

गौरेला पेंड्रा मरवाही। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में आज व्यापंम ने प्रवेश परीक्षा के लिए प्री बीएड एग्जाम का आयोजन किया। जिसके लिए जिले में 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए। इन परीक्षा केंद्रों में 2800 परीक्षार्थी भाग लेंगे। गर्मी को देखते हुए प्रशासन के इंतजाम की बात कह रहा है। परीक्षा दो पालियों में आयोजित की गई है। पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के नोडल अधिकारी आनंद रूप तिवारी ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा कर्मियों और शिक्षकों की भर्ती में बीएड की अनिवार्यता होने की वजह से बीएड परीक्षार्थियों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। बीएड में प्रवेश के प्री बीएड परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। जिसके लिए आज जिले में 28 परीक्षार्थी डीएड में प्रवेश के लिए भाग ले रहे हैं। इन परीक्षार्थियों के लिए 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जिन की निगरानी के लिए प्रशासन ने पुख्ता तैयारियां कर रखी हैं। दो पालियों में होने वाली परीक्षा में लगातार निगरानी रखी जाएगी। जिसके लिए प्रशासन पहले ही कमरकस के तैयार है।

घर में रखा गैस सिलेंडर फटने से लगी भीषण आग, पूरे इलाके में मचा हड़कंप

कोरबा। कोरबा के मानिकपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत मुड़ापार बस्ती में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां एक घर में गैस सिलेंडर अचानक ब्लास्ट होने से आग लग गई। धमाका इतना तेज था कि घर में रखे समान के परखच्चे उड़ गए। दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना शुक्रवार रात करीब 10 बजे की है। घर में जुनैद खान की मां, पत्नी और दो बच्चे मौजूद थे। सभी खाना खा रहे थे, इसी दौरान गैस सिलेंडर के पाइप से रिसाव होने लगा और अचानक आग लपटे बढ़ने लगी। आग की लपटे बढ़ते देख परिजनों ने किसी तरह गैस सिलेंडर पर लगे आग पर काबू पाने की कोशिश की। लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। जिसके बाद सभी लोग घर से बाहर भागे, जिसके बाद सिलेंडर में जोरदार धमाका हुआ। घर में रखे सामान के परखच्चे उड़ गए, दीवार में दरार आ गई। आग की सूचना दमकल विभाग को दी गई। दमकलकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का काम शुरू किया।

कोरबा में मिली दुर्लभ उड़ने वाली गिलहरी

कोरबा। किंग कोबरा वाले जिले की उपलब्धि में एक और नाम जुड़ गया है। यहां दुर्लभ उड़ने वाली गिलहरी देखने को मिली है। उड़ने वाली गिलहरी कहां से आई ये पता नहीं चल पाया है क्योंकि एक ट्रक में मिली थी। वन विभाग ने उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया है। शनिवार को ट्रांसपोर्ट नगर के रिहायशी इलाके में ट्रक चालकों ने ट्रक में एक अजीब जीव देखा। जिसे वे पहचान नहीं पाए। कहीं दूर से आने के चलते जीव भी काफी डरा हुआ था। कुछ ही देर में लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसी दौरान किसी ने वन विभाग की वन्य जीव संरक्षण टीम को सूचना दी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अनोखे जीव की पहचान की। वन विभाग की टीम ने बताया कि ये उड़ने वाली गिलहरी है। जो दुर्लभ रूप में पाई जाती है। इसके बाद टीम ने उसे पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। बता दें कि कोरबा में कई दुर्लभ प्रजाति के सांपों के साथ ही किंग कोबरा का बसेरा है। इन सांपों को सुरक्षित करने नेशनल हाइवे अथॉरिटी हाइवे पर बनने वाली सड़क पर टनल बनाने की योजना बना रहा है।

महापौर और विधायक निवास के सामने सड़कों का मेकअप

दुर्ग। आगामी विधानसभा चुनाव देखते हुए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी जनता के लिए सक्रिय हो गई है, वही पिछले कई सालों से जनता की परेशानियों से जनप्रतिनिधियों को कोई वास्ता नहीं था, लेकिन जैसे-जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, जनप्रतिनिधि व बड़े नेता सक्रिय हो गए हैं, दुर्ग जिले की सड़को की ही यदि बात की जाए तो शहर के कई गली मोहल्ले ऐसे हैं, जहां की सड़कें आज भी बद से बदतर स्थिति में हैं, वही विधायक और महापौर के नए निवास की बात करें तो सड़कें बिल्कुल चकाचक हो गई है लेकिन अन्य क्षेत्रों की बात करें तो सड़कों की आज भी वही स्थिति है जो पहले थी, सड़कों पर चलते समय यह नहीं पता चलता कि सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों पर सड़क है, अमूमन शहर के काफी क्षेत्रों की सड़कें आज भी बदहाल स्थिति पर है जब भी कभी कोई बड़े नेता का आगमन होता है तब तब सड़कों लीपापोती कर सच्चाई को छुपाने का प्रयास किया जाता है, बाद में स्थिति जस की तस हो जाती है।

जोन स्तर पर कांग्रेस ने शीर्ष नेताओं को बूथ पुनर्गठन की सौंपी जिम्मेदारी

■ **बूथ स्तर पर पार्टी की मजबूती के चलाया जा रहा बूथ सशक्तिकरण अभियान : शरद लोहाना**

धमतरी। आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के पूर्व कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में भर में लगातार बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने कार्य कर रही है. धमतरी विधानसभा में भी संगठन की मजबूती के दृष्टिकोण से जोन स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है. जिससे बूथ कांग्रेस कमेटी कार्यकारणी गठन की समीक्षा के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं साथ क्षेत्र की राजनीतिक परिस्थितियों को समझा जा सके. जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शरद लोहाना ने धमतरी विधानसभा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अंतर्गत आने वाले सभी 8 जोन कांग्रेस कमेटी में विधानसभा के शीर्ष नेताओं को प्रभारी नियुक्त किया है. जिनके द्वारा बूथ स्तर पर बैठक आयोजित कर बूथ कांग्रेस कमेटी के पुनर्गठन करने के साथ-साथ सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों के मध्य प्रभावी तरीके से पहुंचाने के लिए कार्य किया जाएगा। जिसमे आछोटा जोन प्रभारी दिव्यांगजन सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष मोहन लालवानी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरमिदर छाबड़ा, पेखन लाल साहू, बीसेलाल साहू, देमार जोन प्रभारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष, पूर्व विधायक गुरमुख सिंह होरा, जिला कांग्रेस कमेटी महामंत्री नरेश जसूजा, अमरदीप साहू, संतोष सिन्हा, अमलीडीह जोन पूर्व विधायक हर्षद मेहता, वरिष्ठ कांग्रेस नेता अरविंद दोषी, दामोदर पुरी गोस्वामी, ब्लॉक कांग्रेस ग्रामीण महामंत्री युवराज शर्मा, आमदी जोन महापौर विजय देवांगन

जिला महामंत्री प्रकाश पवार परसतराई सरपंच परमानंद आडील, अध्यक्ष प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति लोहरसि कुबेर गंजीर, छाती जोन जिला पंचायत उपाध्यक्ष निशु चंद्राकर, सरपंच संघ अध्यक्ष धमतरी राजेश चंद्राकर अध्यक्ष प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति भोथली मोहित साहू, वरिष्ठ कांग्रेस नेता झिरिया श्रीराम सिन्हा, दोनर जोन दुग्ध महासंघ अध्यक्ष विपिन साहू, जिला महामंत्री आलोक जाधव, ब्लॉक कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष घनश्याम साहू, मंडी सदस्य कुबेर चन्द्राकर, डाही जोन जिला पंचायत सभापति कविता योगेश बाबर, जिला कांग्रेस कमेटी सचिव दयाराम साहू, अध्यक्ष प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति डाहि टीकाराम साहू, मोंगरागहन जोन प्रभारी अध्यक्ष कृषि उपज मंडी धमतरी ओमकार साहू, जिला महामंत्री अनिता ठाकुर, ब्लॉक कांग्रेस ग्रामीण महामंत्री सत्यवान ध्रुव आदि, अछोटा जोन अध्यक्ष जीवराखन देवांगन, सेक्टर अध्यक्ष लिलर सूर्या नेताम, आछोटा अरुण देवांगन, रुद्री केशव साहू, सोरम अर्जुन साहू, जोन अध्यक्ष देमार दिनेश साहू, सेक्टर अध्यक्ष देमार रघुवीर रामटेके, डोमा डॉ. दयालाल साहू, पिपरछेड़ी दे. संतोष हिरवानी, जोन अध्यक्ष आमदी मनोज साहू, सेक्टर अध्यक्ष आमदी गजेंद्र कुम्भकार, मुजगहन बलराम साहू, पोटियाडीह दिलीप साहू, जोन अध्यक्ष अमलीडीह नीलमणी साहू, सेक्टर अध्यक्ष तरसिंवा नरसिंग साहू, कुर्रा रंजीत साहू, भानपुरी शत्रुघन साहू, जोन अध्यक्ष छाती राकेश देवांगन, सेक्टर अध्यक्ष डोड़की गेंदलाल साहू, बोडरा सा. हरीशचंद्र साहू, छाती चैतराम साहू, कंडेल कोमल प्रजापति, जोन अध्यक्ष डाहि ओमप्रकाश सेन।

सहकारी समिति के कर्मचारी अनिश्चित कालीन हड़ताल पर, खाद-बीज के लिए भटक रहे किसान

बेमेतरा। सहकारी समिति के कर्मचारी अपनी मांगों को अनिश्चित कालीन हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से खेती-किसानी के समय किसानों को खाद-बीज के लिए भटकना पड़ रहा है। यहां सहकारी समिति के मुख्य गेट पर ताला लगा हुआ है। क्षेत्र के किसानों ने किसान नेता योगेश तिवारी को अपनी परेशानियों से अवगत कराया । किसान नेता को बताया कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से अंचल के किसान धान, बीज एवं खाद के लिए भटक रहे हैं ।

क्षेत्र के किसान खाद व बीज के लिए समिति आ रहे हैं लेकिन समितियों में ताला लटका होने के कारण किसानों को बैरंग लौटना पड़ रहा है । जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है । किसान केशलाल साहू सिंघौरी, हरिचंद्र कोसले सरदा, हरिशंकर तुरकाने,सुनील साहू सरदा, रघुवीर साहू आंदू, जीवन गायकवाड़ किरितपुर, लक्ष्मीनाथ सिन्हा नवागांव, धूमदास टंडन, टोपेंद्र सोनवानी चेटूवा, अभय चालीसा सोंढ रूपनदास पात्रे सोंढ, राजू साहू भिभौरी, प्यारेलाल मार्कण्डेय अतरगढ़ी, राजकुमार सोनवानी ने किसान नेता से मुलाकात कर अपनी परेशानियों से अवगत कराया। किसान नेता योगेश तिवारी ने कहा कि मानसून नजदीक है । अब किसान खेती किसानी में जुट जाएंगे । ऐसी स्थिति में खाद और बीज की व्यवस्था नहीं होने पर किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा । वही समिति की हड़ताल समाप्त नहीं होने पर मजबूरन किसानों को बाजार से महंगे दामों पर खाद और बीज खरीदना पड़ । जिससे खेती की लागत बढ़ने के साथ किसानों को नुकसान उठाना पड़ेगा ऐसी स्थिति में शासन-प्रशासन को किसानों को खाद बीज की आपूर्ति के लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाना जरूरी हो गया है ताकि समय पर किसानों को खाद व बीज की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके । शीघ्र व्यवस्था नहीं बनाने की स्थिति में किसानों के साथ मिलकर सुपर आंदोलन किया जाएगा ।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

कांग्रेस में शामिल होने के बजाय कुएं में कूद जाऊंगा : गडकरी

मुंबई। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता नितिन गडकरी ने कहा है कि एक राजनेता ने एक बार उन्हें कांग्रेस में शामिल होने की पेशकश की थी, जिस पर उन्होंने जवाब दिया था कि वह उस पार्टी का सदस्य बनने के बजाय कुएं में कूदकर मर जाना पसंद करेंगे। नितिन गडकरी ने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने पिछले नौ वर्षों में देश में कांग्रेस के 60 वर्षों के शासन की तुलना में दोगुना काम किया है। नरेंद्र मोदी सरकार के नौ साल पूरे होने के मौके पर महाराष्ट्र के भंडारा में एक सभा को संबोधित करते हुए गडकरी ने भाजपा के लिए काम करने के अपने शुरुआती दिनों को याद किया और पार्टी की यात्रा के बारे में बात की। उन्होंने दिवंगत कांग्रेस नेता श्रीकांत जिचकर द्वारा एक बार दी गई पेशकश को भी याद किया। गडकरी ने कहा, जिचकर ने एक बार मुझसे कहा- आप एक बहुत अच्छे पार्टी कार्यकर्ता और नेता हैं, और यदि आप कांग्रेस में शामिल होते हैं, तो आपका भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं कांग्रेस में शामिल होने के बजाय कुएं में कूद जाऊंगा।

यूसीसी पर बोले प्रमोद कृष्णम भाजपा चतुर पार्टी

नईदिल्ली। समान नागरिक संहिता का मुद्दा देश में एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। इन सबके बीच कांग्रेस की ओर से भी इस पर प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि भाजपा सिर्फ 2024 चुनाव जीतना चाहती है इसलिए यूसीसी के मुद्दे को हवा देने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने सरकार पर ध्रुवीकरण के एजेंडे को भी लागू करने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने यूसीसी को लेकर कहा कि यदि सच्चे मन से राष्ट्रहित में कोई कानून लाने की चर्चा होगी तो हम उस पर विचार करेंगे। हम इसका स्वागत कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि समान नागरिक संहिता का मुद्दा देश में एकरूपता लाने के लिए नहीं बल्कि तीसरी बार सत्ता में आने के लिए उठाया जा रहा है...यूसीसी का खाका तैयार नहीं है। इसलिए, मुझे लगता है कि बीजेपी इस मुद्दे को हवा देना चाहती है और 2024 का चुनाव जीतना चाहती है। यह एक चतुर पार्टी है और इसकी पहेली को समझना आसान नहीं है।

अखिलेश ने बताया लोकसभा में भाजपा को हराने का फार्मूला

नई दिल्ली। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए विपक्षी दल अभी से भाजपा को घेरने की रणनीति बनाने लगे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी इस क्रम में लगातार विपक्षी दलों के नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। हाल ही में अखिलेश ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सभी 80 सीटें जीतने का दावा किया था। अब सपा प्रमुख ने वो फार्मूला भी बताया है जिससे भाजपा को यूपी की सभी लोकसभा सीटों पर हराया जा सकता है। अखिलेश यादव ने कहा, 2024 के लिए मैंने नारा दिया है- 80 हराओ, बीजेपी हटाओ। मैं चाहता हूं कि दूसरे दल बड़े दिल के साथ समाजवादी पार्टी के साथ आएं और यकीन दिलाता हूं कि 80 की 80 सीटों पर हमारी जीत होगी। इस बार भी हमें इस फॉर्मूले पर काम करना चाहिए। कई वरिष्ठ नेताओं से बात करने के बाद यही निष्कर्ष निकला है कि जो दल जहां मजबूत है, वहां उसके उम्मीदवार का समर्थन करना चाहिए।

एक परिवार के अलावा कांग्रेस को कुछ नहीं दिखता: भाजपा

नईदिल्ली। केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलकर प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड सोसाइटी कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। इस मामले को लेकर राजनीति भी जारी है। कांग्रेस जहां सरकार पर पंडित नेहरू का नाम मिटाने का आरोप लगा रही है तो वहीं भाजपा का दावा है कि कांग्रेस को एक परिवार के अलावा कुछ नहीं दिखता। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस एक परिवार से आगे नहीं देख सकती। उन्होंने कहा कि यह एक फैमिली लिमिटेड कंपनी है, एक फैमिली लिमिटेड एंटरप्राइज है। अगर पीएम एचडी देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, चरण सिंह, चंद्रशेखर और अन्य लोगों को सम्मान दिया जाता है, जिन्होंने इस देश में योगदान दिया, लेकिन उन्हें एक परिवार से संबंधित होने का सौभाग्य नहीं मिला, अगर उनके योगदान को एक संग्रहालय में मनाया जाता है तो यह तानाशाही नज़रिया क्यों है?

जबरन धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दे रही है कांग्रेस

बेंगलुरु। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पिछली भाजपा सरकार के कई फैसलों को लगातार पलटा जा रहा है। इसी कड़ी में कर्नाटक मंत्रिमंडल ने भाजपा की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा लाए गए धर्मांतरण रोधी कानून को निरस्त करने का फैसला किया था। अब इसी को लेकर भाजपा ने साफ तौर पर कांग्रेस पर जबरन धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देने का आरोप लगा दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पूछा कि क्या वह जबरन धर्मांतरण के पक्ष में है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि भाजपा जबरन धर्मांतरण के लिए कानून लेकर आई थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस जबरन धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दे रही है, उन लोगों को लाईसेंस दे रही है जो धर्मांतरण करा रहे हैं। मैंने संत गनों से अनुरोध किया है कि हिंदू समाज की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। आप महापंचायत कर कांग्रेस के इस निर्णय के खिलाफ संघर्ष करें।

मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर त्रिपुरा में बोले नड्डा- देश में हुए अभूतपूर्व परिवर्तन

मोदी के नेतृत्व में बदली भारत की तस्वीर और तकदीर

अगरतला। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा त्रिपुरा के दौरे पर है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर उन्होंने आज अगरतला में एक जनसभा को संबोधित किया। भाजपा अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा कि इन 9 सालों में भारत की तस्वीर और तकदीर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व ने बदल डाला है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले भारत का नाम भ्रष्टाचारी देशों में सम्मिलित था। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपीए की सरकार में 2014 में ना जमीन छोड़ी, ना आकाश छोड़ा, ना पाताल छोड़ा, तीनों जगह भ्रष्टाचार ही किया...आज मोदी जी ने 13,125 किलोमीटर की सड़क बनाकर सारे बॉर्डर को सुरक्षित कर दिया है।

नड्डा ने कहा कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को निर्णय लेने वाला और मजबूत देश बना दिया है। उन्होंने कहा कि आज भारत एके-203 जैसी राइफल बना रहा है, प्रचंड हेलीकॉप्टर बना रहा है और हमने आईएनएस विक्रांत जैसा लड़ाकू जहाज भी बना कर दिखा दिया है और

आज वो भारतीय सेना के बेड़े में शामिल है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में, हमारी सीमाओं को सुरक्षित करके भारत की सुरक्षा को मजबूत किया गया है। साथ ही 2014 से विकासवाद, वंशवाद को हरा रहा है, रिपोर्ट कार्ड पॉलिटिक्स, वोट-बैंक पॉलिटिक्स, को हरा रहा है। पिछले 9 वर्षों में देश ने अभूतपूर्व परिवर्तन देखा है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि हम नारा लगाते थे कि एक देश में दो निशान-दो विधान नहीं चलेंगे। इस पर आगे बढ़ते हुए हमने धारा-370 को धराशायी कर दिया और कश्मीर को संपूर्णता के साथ भारत से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि डोकलाम के समय चीन कि फौज खड़ी तो भारत की फौज भी डट कर खड़ी रही और उनको वहीं पर ही रोके रखा।

जेपी नड्डा ने कहा कि हम दसवें नंबर की अर्थव्यवस्था थे लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में हम ब्रिटेन को पछाड़ कर दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत 470 एयरबस विमान खरीदने जा रहा है और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कहते हैं कि वर्ष 2050 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है।

मोदी सरकार का 'मजबूत पहलू' वादों को पूरा करना है: जयशंकर

नयी दिल्ली। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शनिवार को कहा कि लोगों से वादे हर कोई करता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार का ''मजबूत पहलू'' यह है कि वह दी गई समयसीमा में सेवाएं उपलब्ध कराती है और परियोजनाओं को पूरा करती है। उन्होंने मोदी सरकार के नौ साल पूरे होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लोगों तक पहुंचने के अभियान 'संपर्क से समर्थन' के तहत यहां बदरपुर में आयोजित एक समारोह में यह बात कही।

जयशंकर ने बदरपुर में राष्ट्रीय तापविद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) के तापीय विद्युत संयंत्र क्षेत्र में विकसित किए जा रहे इको पार्क में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद संवाददाताओं से कहा, ''चुनाव के बाद, वे (लोगों से किए वादों को) भूल जाते हैं, लेकिन मोदी सरकार में लोग आज (सेवाओं को उपलब्ध होते और परियोजनाओं को) पूरा होते देख रहे हैं।'' दक्षिण दिल्ली से सांसद और भाजपा नेता रमेश बिधूड़ी ने कहा कि इको पार्क का उद्घाटन दिसंबर में किए जाने की

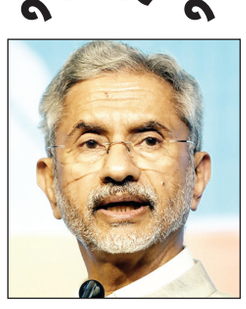

योजना है। जयशंकर ने इस परियोजना के लिए एनटीपीसी और इस तरह की हरित परियोजना पर काम करने के लिए पार्टी सांसदों और स्थानीय नेतृत्व की प्रशंसा की।

उन्होंने कहा, ''यह इको पार्क दिल्ली के लिए नए फेफड़े की तरह होगा। मैं उन सभी को बधाई देता हूं जो इस परियोजना का हिस्सा हैं। यह न केवल प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा, बल्कि इसके आसपास आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर लोगों के जीवन को भी आसान बनाएगा। मोदी सरकार सिर्फ वादे नहीं करती। यह जो काम शुरू करती है उसे एक निश्चित समयसीमा में पूरा करती है।'' बाद में, जयशंकर ने मीडिया से कहा कि वादे तो हर कोई कर सकता है, लेकिन मोदी सरकार का ''मजबूत पहलू'' वादों को ''पूरा करना'' है। जयशंकर ने कहा, ''मोदी सरकार के लिए 'विकास' पहली प्रतिबद्धता है, इसलिए यह प्रतिबद्धताओं का 'तीर्थ' है।'' भाजपा ने 'विकास तीर्थ यात्रा' का आयोजन किया है, जो बदरपुर के इको पार्क से शुरू हुई और जयशंकर तथा भाजपाके कई अन्य वरिष्ठ नेता इसमें शामिल हुए। मंत्री ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि बदरपुर के लोग यह भी देखेंगे कि ''कौन सी सरकार काम करती है और कौन सी सरकार केवल वादे करती है।''

उन्होंने कहा कि एक विदेश मंत्री के रूप में ''मैं आपसे कह सकता हूं कि मैं दुनिया भर के देशों की यात्रा करता हूं, कई शहरों और राजधानियों को देखता हूं।'' उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तौर-तरीकों को भारत में लाया जाए। जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का भी दृष्टिकोण यही है कि ''जब भी वह विदेश में कोई ऐसा काम देखते हैं, जैसे नदी की सफाई या स्टेशन का निर्माण या नयी तकनीक को अपनाना, तो वह उन सर्वोत्तम तरीकों को भारत में भी लाना चाहते हैं।

बंगाल पंचायत चुनाव : सुप्रीम कोर्ट पहुंचा राज्य निर्वाचन आयोग

केंद्रीय बलों की तैनाती के हाईकोर्ट के आदेश का विरोध

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग ने कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बता दें कि कोलकाता हाईकोर्ट ने अपने फैसले में पंचायत चुनाव के दौरान कुछ जिलों में केंद्रीय बलों की नियुक्ति का आदेश दिया था। वहीं बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने पंचायत चुनाव से संबंधित मुद्दे पर चर्चा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के कमिश्नर राजीव सिन्हा को शनिवार को राजभवन तलब किया।

क्या है कोलकाता हाईकोर्ट का आदेश

पंचायत चुनाव में हिंसा की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पंचायत चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती और नामांकन की तारीख बढ़ाने की मांग की थी। इस पर हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग को राज्य पुलिस के साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि इसका अंतिम फैसला राज्य निर्वाचन आयोग का होगा और राज्य सरकार से परामर्श के बाद ही वह इस संबंध में फैसला ले सकेंगे। कोर्ट ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग सभी संवेदनशील जिलों के लिए केंद्रीय बलों की मांग करेगा और इसका खर्च केंद्र सरकार उठाएगी।

हाईकोर्ट में दायर हुई पुनर्विचार याचिका

कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की। ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट से अपने फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कांग्रेस नेता अबू हसीम खान ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान जमकर हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। आरोप है कि उम्मीदवारों को नामांकन ही नहीं करने दिया जा रहा है। अलग-अलग जगहों पर 30 से अधिक हिंसक झड़पों में पांच लोगों की मौत हो चुकी है और 90 से ज्यादा लोग घायल हैं।

बंगाल हिंसा को लेकर राज्यपाल से मिले मजूमदार

कोलकाता। बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक बवाल लगातार जारी है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात के बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि मैंने राज्यपाल को हिंसा के बारे में सब कुछ बता दिया। उन्होंने हमें बताया कि पंचायत चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को रोकने के लिए सभी सक्रिय और प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। पंचायत चुनाव को लेकर टीएमसी नेताओं के साथ सीएम ममता बनर्जी की आगामी बैठक पर मजूमदार ने तंज कसते हुए कहा कि उनकी योजना चल रही है कि दूसरों को नामांकन कैसे वापस लेना है और वोट लूटना है ... वे ये सभी योजनाएं बनाएंगे। इससे पहले सुकांता मजूमदार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनावों की सुरक्षा स्थिति में तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है।

खेल
प्रमुख समाचार

अफगानिस्तान को हराकर बांग्लादेश ने रचा इतिहास

मीरपुर। बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 546 रन के बड़े अंतर से हराकर शनिवार को यहां रनों के लिहाज से टेस्ट में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में रनों के लिहाज से यह तीसरी सबसे बड़ी जीत है। जीत के लिए 662 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए अफगानिस्तान की टीम मैच के चौथे दिन दूसरी पारी में 115 रन पर आउट हो गयी। तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद ने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 37 देकर चार विकेट लिये। नजमुल ने दोनों पारियों में शतक (146 और 124 रन) लगाकर बांग्लादेश की जीत की नींव रखी।

वह मोमिनुल हक के बाद टेस्ट क्रिकेट की दोनों पारियों में शतक जमाने वाले बांग्लादेश के दूसरे बल्लेबाज बन गए। बांग्लादेश की पिछली सबसे बड़ी जीत 2005 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 226 रन से थी। टेस्ट में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड इंग्लैंड ने नाम है जिसने 1928 में ऑस्ट्रेलिया को 675 रन से हराया था। इसके बाद 1934 में द ओवल में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड पर 562 रन की जीत दर्ज की थी। अफगानिस्तान ने दिन की शुरुआत दो विकेट पर 45 रन से की। दिन के तीसरे ओवर में ही इबादत हुसैन (22 रन पर एक विकेट) ने नासिर जमाल (छह रन) को विकेटकीपर के हाथों कैच करा दिया। रहमत शाह (30 रन) एक छोर पर डटे रहे तो वहीं दूसरे छोर से शरीफुल इस्लाम (28 रन पर तीन विकेट) ने अफसर जजाई (छह) और और बाहिर शाह (सात) को चलता किया। बाहिर कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी की जगह बल्लेबाजी के लिए आये थे। शाहिदी तस्कीन की बाउंसर पर तीसरे दिन चोटिल होने के बाद 13 रन पर रिटायर हर्ट हुए थे। तस्कीन ने रहमत को आउट कर टीम की बड़ी जीत सुनिश्चित कर दी। उन्होंने इसके बाद करीम जन्नत (18) और यामीन अहमदजई (एक) को भी पवेलियन की राह दिखायी।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

अडानी पोर्ट-एयरपोर्ट के बाद रेलवे सेक्टर में जमाएंगे सिक्का

नई दिल्ली। अडानी ग्रुप एक और बड़ी डील करने जा रहा है। पहले से ही पोर्ट और एयरपोर्ट पर दबदबा रखने वाले गौतम अडानी अब रेलवे का रुख कर रहे हैं। गौतम अडानी ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म को खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। उद्योगपति गौतम अडानी अब रेलवे सेक्टर में भी धमाल मचाने की तैयारी कर रहे हैं। मौजूदा वक्त में देश की सबसे बड़ी पोर्ट और एयरपोर्ट ऑपरेटर करने वाले अडानी ग्रुप ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म में 100 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज रेल टिकट बुकिंग सेगमेंट में बड़ा निवेश करने जा रही है। अडानी ग्रुप ने रेलवे सेक्टर में अपना सिक्का जमाने की बड़ी शुरुआत ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग के जरिए की है। गौतम अडानी की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज स्टार्क एंटरप्राइजेज में 100% हिस्सेदारी खरीदने जा रही हैं।

सेविंग अकाउंट पर पांच बैंक दे रहे 7 फीसदी तक ब्याज दर

नईदिल्ली। आज के समय में तकरीबन हर व्यक्ति के पास बैंक अकाउंट है। सेविंग अकाउंट खुलवाना फाइनैंशियल दुनिया में कदम रखने का पहला पड़ाव है। सेविंग अकाउंट में रखा पैसा सुरक्षित भी रहता है और उस पर ब्याज भी मिलता है। हालांकि मुख्यधारा के बैंकों में सेविंग अकाउंट पर बहुत अधिक ब्याज नहीं मिलता है। इसलिए अगर आप अपने पैसे पर ज्यादा ब्याज चाहते हैं तो स्मॉल फाइनैंस और पेमेंट बैंक आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं। आज की डिजिटल दुनिया में स्मॉल फाइनैंस और पेमेंट बैंकों के पास कम लागत, उच्च तकनीक-सक्षम व्यवसाय मॉडल हैं, जिसके कारण वे ग्राहकों को बेहतर सर्विस दे सकते हैं। सेविंग अकाउंट पर एयरटेल पेमेंट्स बैंक, एयू स्मॉल फाइनैंस बैंक, ESAF स्मॉल फाइनैंस बैंक, फिनकेयर स्मॉल फाइनैंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनैंस बैंक 7 फीसदी तक ब्याज की पेशकश कर रहे हैं।

शेयर बाजार, मध्यवर्ती नए उत्पादों से धनशोधन के जोखिम चिह्नित करें: सेबी

नयी दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शेयर बाजारों एवं बाजार मध्यवर्तियों को नए उत्पादों के विकास और नए कारोबारी तौर-तरीकों से धनशोधन और आतंकवाद का वित्तपोषण होने से संबंधित जोखिमों को चिह्नित करने के लिए कहा। इसके अलावा, सेबी ने धनशोधन रोधी मानकों और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के संबंध में प्रतिभूति बाजार मध्यवर्तियों के दायित्वों पर जारी अपने नए दिशानिर्देशों में उन्हें ऐसे उत्पादों, प्रक्रियाओं, सेवाओं और प्रौद्योगिकियों को पेश करने व उनका उपयोग करने से पहले ऐसे जोखिम का प्रबंधन करने का निर्देश दिया। सेबी ने यह कदम सरकार के मार्च में धनशोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) में संशोधन करने के बाद उठाया है।

प्रौद्योगिकी की मदद से जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया मजबूत करे : वित्तमंत्री

नयी दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर अधिकारियों को प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक मजबूत बनाने के लिए कहा। सीतारमण ने जीएसटी के फर्जी पंजीकरण और गलत बिल बनाने को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में कर अधिकारियों को यह निर्देश दिया। वित्त मंत्री के कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा, निर्मला सीतारमण ने निर्देश दिया कि जीएसटी पारिस्थितिकी तंत्र में ऐसी फर्जी फर्मों का प्रवेश रोकने के लिए जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया को प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से अधिक मजबूत किया जा सकता है। वित्त मंत्री ने नकली फर्मों को खत्म करने के लिए चलाए गए विशेष अभियान के उद्देश्यों के बारे में बताने के लिए देशव्यापी अभियान चलाने का आह्वान किया।

रक्षा क्षेत्र में बढ़ता उत्पादन भारत को बनाएगा 5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था

प्रह्लाद सबनानी

भारत कुछ समय पूर्व तक रक्षा के क्षेत्र में पूर्णत: आयातित उत्पादों पर ही निर्भर रहता था। छोटे से छोटा उत्पाद भी विकसित देशों से आयात किया जाता रहा है। परंतु, हाल ही के समय में भारत ने सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की ओर अपने कदम बढ़ा दिये हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक जानकारी के अनुसार, भारत में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान रक्षा क्षेत्र से जुड़े उत्पादों का उत्पादन 1.07 लाख करोड़ रुपये के मूल्य का रहा है। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि देश में रक्षा क्षेत्र से जुड़े उत्पादों के उत्पादन का मूल्य एक लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया है। यह राशि 1200 करोड़ अमेरिकी डॉलर के बराबर है। जबकि वित्तीय वर्ष 2021-22 में रक्षा क्षेत्र से जुड़े उत्पादों का उत्पादन 95,000 करोड़ रुपये का रहा था। इस प्रकार, भारत रक्षा क्षेत्र में घरेलू उत्पादन बढ़ाकर आत्मनिर्भरता की ओर मजबूती से आगे बढ़ रहा है।

अभी हाल ही में रक्षा विभाग ने 928 उत्पादों की एक सूची जारी की है, इस सूची में दिए गए समस्त उत्पादों का निर्माण अब पूर्णत: भारत में ही किया जाएगा एवं आगामी वर्षों में इन उत्पादों का आयात पूर्णत: बंद कर दिया जाएगा। वर्तमान में इन उत्पादों पर 715 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है। उक्त सूची में वर्णित उत्पादों को भारत में ही निर्माण की मंजूरी भी दे दी गई है। इस प्रकार की तीन सूचियां पूर्व में भी रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की जा चुकी है। केंद्र सरकार के इस क्रांतिकारी निर्णय से रक्षा क्षेत्र से जुड़े उत्पादों का निर्माण अब भारत में ही होने लगा है एवं पूर्व में इन उत्पादों के आयात पर भारी भरकम विदेशी मुद्रा खर्च की जाती

थी, अब उस विदेशी मुद्रा की भी देश को बचत हो रही है।

केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र के उत्पादों का आयात लगातार कम करते हुए अब कई रक्षा उत्पादों का निर्यात प्रारम्भ कर दिया है। अभी हाल ही में भारत का स्वदेशी निर्मित तेजस हल्का लड़ाकू विमान मलेशिया की पहली पसंद बनाकर उभरा है। मलेशिया ने अपने पुराने लड़ाकू विमानों के बेड़े को बदलने के लिए प्रतिस्पर्धा की थी। जिसमें चीन के जेएफ-17, दक्षिण कोरिया के एफए-50 और रूस के मिग-35 के साथ साथ याक-130 से कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद मलेशिया ने भारतीय विमान तेजस को पसंद किया है। आकाश मिसाइल भी भारत की पहचान है एवं यह एक स्वदेशी (96 प्रतिशत) मिसाइल है। दक्षिणपूर्व एशियाई देश वियतनाम, इंडोनेशिया, और फिलिपींस के अलावा बहरीन, केन्या, सउदी अरब, मिस्र, अल्जीरिया और संयुक्त अरब अमीरात ने आकाश मिसाइल को खरीदने में अपनी रुचि दिखाई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट रक्षा क्षेत्र के लिए भी एक बड़ी सौगात लेकर आया है। केंद्रीय बजट में वर्ष 2023-24 के लिए रक्षा क्षेत्र को कुल 5.94 लाख करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, जो कुल बजट की राशि का 8 प्रतिशत है। बजट में आवंटित की गई इस राशि का उपयोग हथियारों की आत्मनिर्भर तकनीक और भारत में ही इन उत्पादों के निर्माण के कार्य पर किया जाएगा। इससे देश में ही रोजगार के लाखों नए अवसर निर्मित होंगे।

चूंकि भारत सरकार द्वारा रक्षा क्षेत्र से जुड़े उत्पादों को भारत में ही निर्मित करने हेतु प्रोत्साहन दिया जा रहा है तथा रक्षा उत्पादों का भारत में ही निर्माण एवं भारत से निर्यात जिस तेज गति से आगे बढ़ रहा है इससे अब यह आभास होने लगा है कि वर्ष 2027 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर तक पहुंचाने में, आगे आने वाले समय में, देश का रक्षा क्षेत्र भी प्रमुख भूमिका निभाने जा रहा है। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 3.50 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का है। वर्ष 2031 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 7.5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर तक पहुंच जाने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है और इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था अमेरिका एवं चीन के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी।

जर्मनी के साथ संबंधों पर तनाव की छाया

शोभना जैन

सात माह की दुधमुंही अरिहा शाह को बीस माह पहले जर्मनी की बाल कल्याण सेवा द्वारा अपनी कस्टडी में लेने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसकी छाया द्विपक्षीय संबंधों पर भी दिखाई दे रही है। मां-बाप की गुहार और भारत सरकार के बार-बार आग्रह के बावजूद वहां की बाल कल्याण सेवा बच्ची की कस्टडी मां-बाप को सौंप नहीं रही है, हालांकि वहां की पुलिस ने फरवरी 2022 में बच्ची के मां-बाप के खिलाफ आपराधिक केस को बंद कर दिया लेकिन कस्टडी का मामला हल नहीं हुआ और इसके लिए लड़ाई जारी है। जर्मनी के एक अस्पताल ने भी बच्ची के खिलाफ किसी प्रकार के यौन उत्पीड़न होने के आरोपों को खारिज कर दिया है, लेकिन चाइल्ड लाइन सर्विस ने कोर्ट में माता-पिता के अभिभावक होने संबंधी अधिकार रद्द किए जाने का केस बरकरार रखा यानी बच्ची पिता भावेश और माता धरा शाह को नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने अरिहा शाह के अभिभावकों की मनोवैज्ञानिक जांच कराने की बात कही लेकिन अब सवा दो बरस की हो चुकी बच्ची एक अजनबी देश, अजनबी माहौल और अनजान परिवेश में अपने मां-बाप के प्रेम को तरस रही है। दोनों देशों के बीच यह मामला राजनयिक तनाव का रूप लेता जा रहा है लेकिन बच्ची की कस्टडी के लिए जर्मनी में दर-दर भटकने वाले माता-पिता जर्मन अधिकारियों से गुहार लगाने और भारत सरकार द्वारा भी बच्ची को भारत को अविलंब सौंपे जाने की मांग के बावजूद अभी तक कस्टडी नहीं मिलने से निराश हैं। गुजराती मूल के जर्मनी में रहने वाले धरा और भावेश शाह की बेटी अरिहा शाह की कस्टडी के मामले पर विदेश मंत्री डॉ। एस। जयशंकर ने अपनी जर्मनी यात्रा में जर्मनी के अधिकारियों को अरिहा के माता-पिता के साथ ही देश की चिंता से भी अवगत कराया। जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक की गत दिसंबर में भारत यात्रा के दौरान भी भारतीय प्रतिनिधियों ने अरिहा की कस्टडी अविलंब भारत को सौंपे जाने की मांग की। अरिहा शाह के समर्थन में 59 सांसदों ने भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन को एक पत्र लिख कर भारत की चिंता से अवगत कराया और बच्ची की कस्टडी तुरंत भारत को सौंपे जाने की मांग की। लेकिन इन तमाम प्रयासों के बावजूद बच्ची मां के आंचल से दूर फॉस्टर होम में पल रही है। बच्ची की कस्टडी की कानूनी लड़ाई जारी है। गौरतलब है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर भावेश और उनकी पत्नी धरा शाह साल 2018 में जर्मनी गए थे, वहीं उनकी बेटी का जन्म हुआ, मां-बाप पर लगे आरोपों के बाद से उनकी बेटी अरिहा शाह पिछले 20 महीने से जर्मनी के फोस्टर केयर में ही है। बच्ची की मां धरा शाह का कहना है कि एक मां की अपने बच्चे को पलते-बढ़ते देखने की ख्वाहिश होती है लेकिन उन्हें इन सब लम्हों से दूर कर दिया गया है। मेरी बेटी सवा दो साल की हो चुकी है। न मैंने उसके मुंह से निकला पहला शब्द सुना, चलना सीखने से पहले न पहला कदम देखा और न उसके दांत निकलना देखा। धरा शाह कहती हैं कि जब वो अपनी बेटी से मिलने जाती हैं तो वो हम से बहुत प्यार से मिलती है, लेकिन इस पर जर्मनी का प्रशासन कहता है कि उसे स्ट्रेंजर अटैचमेंट डिसऑर्डर है।

राजस्थान में मोदी की प्रतिष्ठा दांव पर

समीर चौगांवकर

नरेंद्र मोदी सरकार के नौ साल पूरे होने पर भाजपा ने एक महीने के महाजनसंपर्क अभियान के श्रीगणेश का जो प्रस्ताव मोदी को भेजा था उसमें मोदी की रैली हैदराबाद में आयोजित करने का प्रस्ताव था। मोदी ने इसे बदलकर राजस्थान के अजमेर में रखने को कहा। इसके पीछे मोदी का संदेश साफ था कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रचार का नेतृत्व वह खुद करेंगे और अशोक गहलोत से सीधे दो दो हाथ करेंगे। पिछले आठ महीने में जिस तरह से उन्होंने पांच रैलियां राजस्थान में की है वैसे ही अपनी सरकार के नौ साल पूरे होने के उपलक्ष में छठी रैली अजमेर में करके राजस्थान की चुनावी कमान अपने हाथ में ले ली। 31 मई को अजमेर में रैली कर मोदी ने बता दिया कि 2023 के अंत में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए सेमीफाइनल जैसे हैं, जिन्हें मोदी किसी भी स्थिति में हारना नहीं चाहते हैं। राजस्थान में जीत मोदी की 2024 में वापसी में महत्त्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है, वहीं राजस्थान में भाजपा की विफलता मोदी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है।

प्रधानमंत्री मोदी के राजस्थान दौरे की शुरुआत 30 सितंबर 2022 को हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिरोही जिले के आबू रोड में सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम बनाया था। हालांकि अपेक्षा से बहुत कम लोग जुटने के कारण मोदी रात दस बजे के बाद ही सभास्थल पहुंचे और वहां उपस्थित लोगों से लाउडस्पीकर उपयोग की समय सीमा समाप्त हो जाने के कारण भाषण नहीं दे पाने के लिए माफी मांग ली। इस सभा से उन्होंने दक्षिणी राजस्थान के सिरोही, जालोर और पाली सहित आसपास के जिलों की 26 सीटों को साधने का प्रयास किया था। दक्षिण राजस्थान का यह इलाका भाजपा के लिए मजबूत माना जाता है। यहां की 26 में से पिछली बार भाजपा ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी। दूसरी बार पीएम मोदी ने एक नवंबर 2022 को बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में सभा कर आसपास की 19 सीटों को साधा था। तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी ने 8 जनवरी 2023 को भीलवाड़ा में गुर्जर समाज के आराध्य देव देवनारायण भगवान की जयंती समारोह में शामिल होकर भीलवाड़ा के आसींद में सभा की थी। यहां से उन्होंने गुर्जर समाज को भाजपा का साथ देने का संदेश दिया था।

चौथी बार 12 फरवरी, 2023 को मोदी दौसा जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के मौके पर आए। यहां मोदी ने पूर्वी राजस्थान के आठ जिलों दौसा, करौली, भरतपुर, टोंक, जयपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, धौलपुर की 58 विधानसभा सीटों को साधने के लिए गुर्जर-मीणा बहुल दौसा में सभा की थी। पांचवी बार 10 मई, 2023 को पीएम मोदी ने नाथद्वारा और आबूरोड में बड़ी सभाओं को संबोधित किया था। छठी बार 31 मई, 2023 को मोदी ने अजमेर में रैली की थी। अजमेर रैली से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में दर्शन भी किया था। यहां से मोदी ने पूरे राजस्थान में भाजपा के मूल एजेंडे हिंदुत्व का संदेश देने की कोशिश की थी। आठ महीने में मोदी के राजस्थान दौरों का आकलन किया जाए तो वे लगभग 100 विधानसभा सीटों को कवर कर चुके हैं। मोदी का अब तक का राजस्थान दौरा जाति-समाजों को साधने के मकसद से ही हुआ है। उनका फोकस आदिवासी, ओबीसी, गुर्जर-मीणा और एससी समुदाय रहा है। कर्नाटक चुनाव में भाजपा की शर्मनाक हार के बाद प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान में हर हाल में सरकार बनाने की रणनीति बनाने में जुटे हैं। भाजपा संगठन राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी की सभाएं राजस्थान के हर जिले में करवाने पर विचार कर रहा है। संभवत: भाजपा देश में ऐसा पहली बार प्रयोग करने जा रही है जब किसी चुनावी राज्य के हर जिले में प्रधानमंत्री सभा करेंगे। हालांकि गुटबाजी में फंसी प्रदेश भाजपा मोदी की अब तक की 6 रैलियों में अपेक्षा अनुरूप भीड़ जुटाने में बार बार विफल रही है। इसलिए राजस्थान को लेकर भाजपा की रणनीति साफ है कि राजस्थान के चुनाव में मोदी ही भाजपा का चेहरा होंगे। बाकी गुटों में बंटे नेता मोहरे तो हो सकते हैं मुख्य चेहरा नहीं। भाजपा का आकलन है कि अगर पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है तो प्रदेश के नेताओं में चल रही गुटबाजी का असर चुनावों पर नहीं पड़ेगा और सभी गुट एकजुट होकर चुनाव लडेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी की नजर राजस्थान विधानसभा चुनाव के कुछ माह बाद होने वाले लोकसभा चुनावों पर भी है। पिछले दो लोकसभा चुनावों में बीजेपी एवं सहयोगी दल ने राजस्थान की 25 में से 25 लोकसभा सीटें जीती थी। मोदी राजस्थान विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने के साथ साथ उसके तुरंत बाद होने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में भी सभी सीटें लगातार तीसरी बार जीतना चाहते हैं। दरअसल, राजस्थान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी इतने गंभीर क्यों है, इसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान के 33 जिलों में से 7 जिलों में भाजपा का खाता भी नहीं खुला था। वैसे वसुंधरा राजे के नेतृत्व में ही लड़े गए 2013 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने 200 में से 163 सीटें जीतकर रिकॉर्ड कायम किया था। लेकिन 2018 में मोदी और वसुंधरा के बीच बढ़ गए तनाव के बीच हुए चुनावों में भाजपा और संघ के कार्यकर्ताओं ने ही मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं के नारे लगाकर भाजपा को ही सत्ता से बाहर कर दिया।

2018 में मोदी और अमित शाह ने राजस्थान के चुनाव जीतने में कोई विशेष रुचि भी नहीं दिखाई थी, और अनमने ढंग से ही प्रचार किया था। इसके अलावा 60 से भी अधिक सीटों पर भाजपा के कार्यकर्ता ही निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतर गए और भाजपा के वोट काटकर कांग्रेस उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाया। संगठन की ओर से ऐसे निर्दलीय उम्मीदवारों को बिठाने के कोई प्रयास भी नहीं किए गए। इसके बावजूद 2018 में भाजपा को मिले कुल वोट और कांग्रेस को मिले कुल वोट में मात्र आधा प्रतिशत का फर्क रहा। आत्मघाती मानसिकता के साथ आधे अधूरे मन से लड़े गए 2018 के चुनावों में भाजपा का खाता जिन जिलों में नहीं खुला था उनमें सीकर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, प्रतापगढ़ और जैसलमेर शामिल है। इनमें से 4 जिले पूर्वी राजस्थान के हैं। इसके अलावा 4 जिले ऐसे हैं, जहां बीजेपी 70 से 80 प्रतिशत तक सीटें हार गई थी। इनमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत का गृह जिला जोधपुर भी शामिल है। यहां बीजेपी को 10 में से 2 सीटें ही मिली थी। बाकी 8 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं, नागौर जिले में भी बीजेपी का यही हाल हुआ। नागौर में बीजेपी 10 में से केवल 2 सीटें ही जीत पाई थी। अलवर जिले की 11 में से भी 9 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। अलवर से बीजेपी के केवल दो विधायक हैं। नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ के गृह जिले चुरू में भी पिछले विधानसभा चुनावों में बीजेपी 6 में से 2 सीटें ही जीत पाई थी। इसके अलावा जयपुर जिले की 19 में से 6 सीटें ही बीजेपी के खाते में गई थी। दरअसल राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच खिंची तलवारों से राजस्थान कांग्रेस में आए संकट को मोदी एक अवसर के रूप में देख रहे हैं। इसलिए राजस्थान में हुई रैलियों में अशोक गहलोत सरकार में हुए भ्रष्टाचार और आपस की लड़ाई में जनता के हो रहे बुरे हाल का जिक्र कर रहे हैं। कर्नाटक चुनाव को राष्ट्रीय मुद्दों पर बनाकर हार चुकी भाजपा अब राजस्थान में स्थानीय मुद्दों को आगे कर कांग्रेस को पटकनी देने की रणनीति बना रही है। इस कारण राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता के खिलाफ माहौल बनाने के साथ पूरे कैंपेन को स्थानीय मुद्दों पर फोकस करने की रणनीति पर काम कर रही है। मोदी के लिए चुनौती यही है कि वे स्थानीय मुद्दों पर अशोक गहलोत को कितना घेर पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी आस लगाए बैठी है कि मोदी के करिश्मे के कारण राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा के पक्ष में एक और तर्क दिया जा रहा है कि 1998 के बाद से राजस्थान में कोई भी सरकार दूसरी बार रिपीट नहीं हुई है। ऐसे में भाजपा की सत्ता में वापसी की उम्मीदें बढ़ी हुई है। वहीं अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस भी जनकल्याणकारी योजनाओं और वादों के दम पर सत्ता में बरकरार रहने की हर संभव कोशिश कर रही है। राजस्थान में सत्ता बदलती है या सत्ता बदलने का रिवाज, इसे देखने के लिए नवबंर या दिसंबर तक इंतजार करना होगा जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव होंगे।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

गायत्रीरहस्योपनिषद् (भाग-4)

गतांक से आगे...

(अब चौबीस पातकों का वर्णन करते हैं-) सभी पातक, उपपातक, महापातक, अगम्यागमन (जिनसे योनि सम्बन्ध नहीं होना चाहिए, उनसे योनि सम्बन्ध रखना आदि), गोहत्या, ब्रह्महत्या, भ्रूणहत्या (गर्भपात), वीरहत्या, पुरुष हत्या, कई जन्मों से की हुई हत्यायें, स्त्रीहत्या, गुरुहत्या, पितृहत्या, आत्मघात, चर तथा अचर आदि जीवों की हत्या, जो खाने के लायक नहीं, उन्हें खाने में होने वाली हत्या, दान ग्रहण का पाप, अपने कर्म का त्याग, स्वामी की सेवा से पराङ्मुख कर्म जन्य पाप, दूसरों के धन को चुराने से होने वाला पाप, शूद्र के अन्न को ग्रहण करने से होने वाला पाप, शत्रुघात तथा चाण्डाल से योनि सम्बन्ध रखना आदि इन समस्त पापों के विनाश के लिए हमेशा इन्हें याद रखे।

मैं ऐसी उस वाक् शक्ति की अधिष्ठात्री देवी गायत्री की शरण (आश्रय) को प्राप्त करता हूँ, जिसकी मूर्धा (शिर) ब्रह्मा, शिखान्त (शिखा का अन्त भाग) विष्णु, ललाट (मस्तक) रुद्र, (दोनों) नेत्र-सूर्य और चन्द्रमा, (दोनों) कान शुक्राचार्य एवं बृहस्पति, नासिका के दोनों रन्ध्र (छिद्र) अश्विनीकुमार, दोनों दन्तोष्ठ- दोनों सन्ध्यायें, मुख-मरुत् (वायु), स्तन वसु आदि, हृदय- बादल, पेट आकाश, नाभि अग्नि, कमर-इन्द्राग्नि, जाँघ - प्राजापत्य, उरुद्वय- कैलाश के मूल स्थल, दोनों घुटने- विश्वदेव, जंघाएँ (पिंडली)- शिशिर, गुल्फ (टखने)- पृथ्वी की वनस्पति आदि नख महत् तत्त्व, हड्डियाँ - नवग्रह, अंतड़ियाँ-केतु, मांस- ऋतु संधियाँ, दोनों कालों का गमन बोधक वर्ष संवत्सर और निमेष दिन एवं रात्रि हैं। जो मनुष्य इस गायत्री रहस्य का अध्ययन (पाठ) करता है, ऐसा मानना चाहिए कि उसने तो सहस्रों यज्ञ सम्पन्न कर लिये हैं। जो इस गायत्री रहस्य का पाठ करता है, उसके द्वारा (भूल से) दिन में किये हुए समस्त पापों का उसके पाठ से क्षय (विनाश) हो जाता है। जो प्रात: एवं मध्याह्न काल में इसका पाठ (अध्ययन) करता है, वह अपने छ: मास के किये हुए पापों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है अर्थात् पापरहित हो जाता है। जो प्रतिदिन प्रात: एवं सायंकाल इसका पाठ करे, तो उसके समस्त जन्मों के पाप विनष्ट हो जाते हैं। जो भी ब्राह्मण इस गायत्री रहस्य का पाठ करे, तो यह मानना चाहिए कि उसने गायत्री महामन्त्र का साठ हजार लाख बार जप कर लिया है, उसने सभी (चारों) वेदों का पाठ कर लिया, समस्त तीर्थों में उसने स्नान कर लिया है।

क्रमश:...

फादर्स डे : पिता संस्कारदाता ही नहीं, जीवन-निर्माता भी है

ललित गर्ग

जून महीने के तीसरे रविवार को अंतर्राष्ट्रीय पिता दिवस यानी फादर्स डे मनाया जाता है। इस साल 19 जून 2023 को भारत समेत विश्वभर में यह दिवस मनाया जायेगा। पिता दिवस की शुरुआत बीसवीं सदी के प्रारंभ में पिताधर्म तथा पुरुषों द्वारा परवरिश का सम्मान करने के लिये मातृ-दिवस के पूरक उत्सव के रूप में हुई। यह हमारे पूर्वजों की स्मृति और उनके सम्मान में भी मनाया जाता है। दुनिया के अलग-अलग देशों में अलग-अलग दिन और विविध परंपराओं के कारण उत्साह एवं उमंग से यह दिवस मनाया जाता है। हिन्दू परंपरा के मुताबिक पितृ दिवस भाद्रपद महीने की सर्वपितृ अमावस्या के दिन होता है। पिता एक ऐसा शब्द जिसके बिना किसी के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक ऐसा पवित्र रिश्ता जिसकी तुलना किसी और रिश्ते से नहीं हो सकती। बचपन में जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो सबसे पहले अपने पिता की उंगली थामता है। नन्हा-सा बच्चा पिता की उँगली थामे और उसकी बाँहों में रहकर बहुत सुकून पाता है। बोलने के साथ ही बच्चे जिद करना शुरू कर देते हैं और पिता उनकी सभी जिदों को पूरा करते हैं। बचपन में चॉकलेट, खिलौने दिलाने से लेकर युवावर्ग तक बाइक, कार, लैपटॉप और उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजने तक संतान की सभी माँगों को वो पूरा करते रहते हैं लेकिन एक समय ऐसा आता है जब भागदौड़ भरी इस जिंदगी में बच्चों के पास अपने पिता के लिए समय नहीं मिल पाता है। इसी को ध्यान में रखकर पितृ दिवस मनाने की परंपरा का आरम्भ हुआ। सोनेरा डोड जब नन्ही-सी थी, तभी उनकी मां का देहांत हो गया। पिता विलियम स्मार्ट ने सोनेरो के जीवन में मां की कमी नहीं महसूस होने दी और उसे मां का भी प्यार दिया। एक दिन यूं ही सोनेरा के दिल में ख्याल आया कि आखिर एक दिन पिता के नाम क्यों नहीं हो सकता? इस तरह 19 जून 1910 को पहली बार फादर्स डे मनाया गया। मानवीय रिश्तों में दुनिया में सबसे बड़ा स्थान मां को दिया जाता है, लेकिन एक बच्चे को बड़ा और सभ्य बनाने में उसके पिता का योगदान कम करके नहीं आंका जा सकता। बच्चे को जब कोई खरोंच लग जाती है तो जितना दर्द एक मां महसूस करती है, वही दर्द एक पिता भी महसूस करते हैं। पिता बेटा की चोट देख कर कठोर इसलिये बना रहता है ताकि वह जीवन की समस्याओं से लड़ने का पाठ सीखे, सख्त एवं निडर बनकर जिंदगी की तकलीफों का सामना करने में सक्षम हो। माँ ममता का सागर है पर पिता उसका किनारा है। माँ से ही बनता घर है पर पिता घर का सहारा है। माँ से स्वर्ग है माँ से बैकुंठ, माँ से ही चारों धाम है पर इन सब का द्वार तो पिता ही है। उन्हीं पिता के सम्मान में पितृ दिवस मनाया जाता है। वर्तमान समय के पिता का रूप काफी बदल गया है। पिता बनना आज सिर्फ एक जैविक क्रिया न होकर एक सामाजिक क्रिया भी हो चुकी है। एकल मां की तरह अब समाज में एकल पिता का भी विचार आ चुका है। अब एकल पिता अपने बच्चों का न केवल ख्याल रखते हैं बल्कि उन्हें मां की कमी महसूस नहीं होने देते हैं।

हे एंकरों परलोकपति को तो बख्श दो

बरुण सखाजी

हूं तो इन्हें कौन पकड़कर लाया है परलोक में इंसाफ के देवता परलोकपति ने गुस्से से भौंहें ऊपर करके कहा। महाराज ये... हाथ जोड़कर सामने खड़े दूत प्रमुख ने दूसरे दूत की ओर उंगली दिखाते हुए बोला। महाराज, मैं तो प्रताड़ना अधिकारी से प्राप्त डाटा के अनुसार ही लाया हूं.. मेरा इसमें कोई दोष नहीं। दूसरे दूत ने कहा।

महाराज ने भयानक क्रुद्ध मुद्रा बनाकर दूसरे दूत की ओर देखा। दूत डर गया था। अपनी सफाई इससे अधिक नहीं दे पाया। अब महाराज की क्रुद्ध नजरों का सामना करते हुए उसके पैर थर-थर कांपने लगे। मगर महाराज के सामने खड़ा एक शख्स और लड़की शख्स बिलकुल निश्चिंत खड़े हैं। पुरुष शख्स मुस्कुराता है। पीछे से पब्लिक चिल्लाती है... मारो... मारो।

महाराज बैकफुट पर दिखते हैं, लेकिन उनके दूतों पर वह भयानक क्रोध बरकरार रखते हैं। अपना गदा कंधे पर रखते हुए कहा, तुम निकम्मे दूतों की वजह से आज पब्लिक मेरे ऊपर चढ़ रही है। क्या जरूरत थी इन्हें लाने की। मरने देते वहीं।

लड़की शख्स और पुरुष शख्स फिर मुस्कुराते हैं। महाराज की हालत पतली है। वे तुरंत बड़े महाराज कार्यालय को सूचित करते हैं। बड़े महाराज कार्यालय से अतिरिक्त इंतजाम का आश्वासन मिलता है। महाराज तब तक अपना गदा कंधे पर रखकर पब्लिक का मुकाबला करने के लिए हल्का रौब अधिक भय की मुद्रा में घूमने लगते हैं। शेष सभी दूत उन्हें सुरक्षा कवर इस तरह से देते हुए बल्लम लेकर खड़े हैं जैसे पब्लिक टूट पड़े तो महाराज को अकेला छोड़कर आसानी से पीछे की ओर भागा जा सके। यह बात महाराज भी जानते हैं। इसलिए वे अतिरिक्त सतर्कता के साथ घूम रहे हैं। ऐसी स्थिति में वे भी दूतों के साथ भागेंगे। स्थिति यह घंटों रहती है, तब तक बड़े महाराज कार्यालय से इंतजाम

पहुंचता है। इंतजाम से कुछ शख्स निकलते हैं और पब्लिक की ओर मृत्यु रस फेंकने लगते हैं। चंद सेकेंड्स में मृत्यु रस के प्रभाव से पब्लिक के लोग बेहोश होकर गिर जाते हैं। बड़े महाराज कार्यालय से आए एक अधिकारी ने महाराज की सिंहासन के सामने की सीट ग्रहण की और कहा...बड़े महाराज कार्यालय ने पूछा है आखिर यह बवाल किसके कारण हुआ।

यह सुनते ही दूसरा दूत जो लड़की शख्स और लड़का शख्स को लाया था वह डर गया। गले से थूक सटकाते हुए घबराई मुद्रा में सेंगोल टाइप का डंडा लिए खड़ा रहा। इस डंडे में नंदी के स्थान पर बकरा बना था। इसलिए इसे सेंगोल की बजाए बकरडंड कहना चाहिए। बकरडंड और लोगों के हाथ में भी था, लेकिन यह शख्स बकरडंड से कोई सुरक्षा महसूस नहीं कर रहा था। क्योंकि महाराज ने उसे बुरी तरह से गुस्से में देखा था। बड़े महाराज कार्यालय से आए अधिकारी ने कहा... महाराज मैं आपके दूत का नहीं पूछ रहा। मैं तो जानना चाहता हूं वह कौन लोग हैं जिन्हें लेकर नर्क आई तमाम पब्लिक नारेबाजी कर रही है और आपकी दूत पुलिस उन्हें संभाल नहीं पा रही।

महाराज ने थोड़ा शांति का अनुभव किया। उन्होंने अपनी निगाहें पृथ्वी से लाए गए लड़की शख्स और लड़का शख्स की ओर फेरी। उनके ऐसा करते ही बगल में खड़ा कर्मपोथी इनचार्ज एक छोटे से टैब टाइप के यंत्र को आगे बढ़ाते हुए सेकंड के एक छोटे से हिस्से में कर्म-वीडियो प्ले कर देता है। यहां की व्यवस्था में 100 वर्ष का जीवन-वीडियो महज एक सेकंड के सौवें हिस्से में देखा जा सकता है। यहां के लोग मनुष्यों से एक करोड़ गुना अधिक उन्नत हैं। बड़े महाराज कार्यालय से आए अधिकारी ने पृथ्वी से लाए गए पुरुष शख्स और लड़की शख्स के जीवन-वीडियो देखकर ही तय कर लिया इन पर आरोप क्या हैं और ये किस स्तर के लोग हैं। वह ऐसे अरबों-खरबों लोगों से अब तक मिलता, देखता रहा है, लेकिन माथे पर कभी तनाव नहीं आया। किंतु यहां पहली बार महाराज और बड़े महाराज कार्यालय के इस अफसर के माथे पर पसीने की बूंदें थी। इधर सिंहासन के सामने दरबार के सेंट्रल पोर्च पर हाथों को छाती से बांधे हुए दोनों ही शख्स पुरुष शख्स और लड़की शख्स बेफिक्र खड़े थे। उनके माथे पर कोई अफसोस नहीं था।

इसी बीच पब्लिक के ऊपर फेंका गया मृत्यु रस बेअसर होने लगा। पब्लिक उठने लगी। फिर वही हालात बनने को थे। बड़े महाराज कार्यालय से आया अफसर फिर कुछ इशारा करता है और पब्लिक पर मृत्यु रस की फॉगिंग कर दी जाती है। अब महाराज बड़े महाराज कार्यालय से आए अफसर को बताते हैं।

सर, जो दोनों खड़े हैं ये भारत के न्यूज चैनलों के एंकर रहे हैं।...बड़े महाराज कार्यालय से आए अफसर ने बीच में ही बात काटते हुए कहा... वो तो इनकी मूर्खतापूर्ण मुस्कान से ही लग रहा है। इतना ओवर कॉन्फिडेंस इन्हीं में हो सकता है।

महाराज हल्के हुए और स्माइल देते हुए बोले.. हां तो सर इन लोगों ने पृथ्वी पर भयानक खबरें दिखाई, भयानक अंदाज में दिखाईं। कोई समुद्र में डूबकर हमारे तूफानों की रिपोर्टिंग करता था, कोई कोरोना में पीपीई किट पहनकर स्टूडियो से एंकरिंग करता था। कोई इसरो साइंटिस्ट बनकर स्टूडियो में नाचता था। (लड़की शख्स की ओर इसारा करते हुए।) ये जो छुछूंदर तो स्टूडियो में छाता लेकर बैठ गई थी। पीछे विजुअल चलाकर छाता उड़ाने का नाटक कर रही थी। और ये पुरुष शख्स छोटे बच्चे को भांग देकर नशे की गिरफ्त में बचपन स्टोरी बना रहा था। क्या-क्या गिनाऊं इनका। अब ये जो पब्लिक है वह इनका विरोध कर रही है। पब्लिक कह रही है इन लोगों ने इतना पकाया है कि मरकर भी चैन नहीं मिल सका। पृथ्वी पर तो इनका हम कुछ नहीं कर पाए लेकिन अब हम डरेंगे नहीं, क्योंकि मर चुके हैं अब तो क्या डलना, सोच लिया है छोड़ेंगे नहीं। बस यही मैटर है सर। अब समस्या ये है कि पब्लिक को भी अपन कब तक मृत्यु रस से बेहोश रख पाएंगे। वह जब उठेगी तभी इनकी धुनाई पर आमादा रहेगी। मुझे भी समझ नहीं आ रहा इनका क्या किया जाए। जो कर्मपोथी है उसके हिसाब से इनके पाप इतने भयानक हैं कि हमारे यहां दंड ही नहीं बचा कोई। खतरनाक से खतरनाक दंड भी इनके कर्मों पर फिट नहीं बैठ रहा। प्रताड़ना शाखा ने कुछ खतरनाक दंड़ों का एक महादंड़, कॉम्बो दंड, मिक्स-मैच दंड बनाकर देखा, मगर वह फिट नहीं बैठ पा रहा। आप बड़े महाराज कार्यालय से कहिए ब्रह्म संसद में नया कानून लाएं और उसमें दंड विधान नए सिरे से तय करें। तब तक इन सबको पृथ्वी पर ही रहने दें सर। प्लीज। प्लीज। महाराज ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा।

बापू की दिनचर्या

दिन का भोजन (भाग-7)

गतांक से आगे...

पकने पर उसे खोवे की तरह घोंट दिया जाता, जो बिना चीनी के भी मधुर लगता, कम खाया जाता, विशेष पौष्टिक होता और जिसके सेवन से तोंद नहीं निकलने पाती। बापू मशीन में पिसे हुए आटे और आटे से चोकर अलग करके उपयोग करने के भी पक्ष में नहीं थे। ऐसे आटे को वे सत्त्वहीन (विटामिन-रहित) बताते। इसी कारण आश्रमवासी और बापू शुरू से आटाचक्की चलाते। इससे व्यायाम होता ही, सभी को हाथ-पिसे आटे की स्वास्थ्यवर्द्धक रोटियाँ सुलभ होतीं। आश्रम में आटा चोकर सहित होता। इससे रोटियों में स्वाद और पोषक तत्त्व - दोनों रहते। सन् 1915 में हरिद्वार में कुंभ के अवसर पर बापू ने चौबीस घंटे में पाँच वस्तुओं से अधिक न खाने का व्रत किया। भारत से बाहर पाँच से अधिक वस्तुएँ लेने की उन्होंने छूट रखी। जब उनसे इसका कारण पूछा गया तब उन्होंने बताया कि लोग उनको विशेष स्नेह करते और उनका बहुत ख्याल रखते। तब उनकी प्रसिद्धि इतनी अधिक थी कि वे किसी के मेहमान बनते तो वह उनको नानाविध स्वादिष्ट वस्तुएँ परोसता । बापू अपने को उनके बीच सेवक के रूप में मानते हुए ऐसा करना बहुत अहितकर बताते। इसी कारण उनको दिनभर में पाँच वस्तुएँ लेने की सीमा बाँधनी पड़ी। बापू मानते कि ऐसा करने से उनके एक साथ दो काम सध जाते। नैतिक एवं लौकिक-दोनों दृष्टियों से बापू का व्रत उनके लिए सहायक सिद्ध हुआ। लौकिक दृष्टि यह कि भारत-जैसे गरीब देश में बकरी का दूध हर समय सुलभ नहीं हो पाता तथा अंगूर जैसे फल पैदा करना आसान नहीं। फिर वे अपने को गरीबों से मिलनेवाला आदमी कहते, जिनसे बाहर से मँगाए हुए डिब्बों में सुरक्षित रखे अंगूरों की आशा करना सर्वथा अनुचित होता । व्रत से उनके मितव्ययिता के नियम का पालन हो जाता। बापू के सुबह के भोजन की वस्तुओं का खयाल रखकर उनके शाम के भोजन की तैयारी होती। वे अक्सर सुबह तीन वस्तुएँ और शाम को दो नई वस्तुएँ लेते। भारत में अपने इसी नियम का वे पालन करते। आगा खाँ मह में यदि कभी वे दवा लेने के लिए बाध्य होते तो उसकी गणना भी पाँच चीजों में करते। सन् 32 में यरवदा जेल में वे दिन भर में नमक, सोडा और जल के अतिरिक्त पाँच ही चीजें लेते। भोजन की थाली में जूठन देखकर बापू को कष्ट होता।

क्रमश: ...

शाह के दुर्ग दौरे से नहीं होगी कांग्रेस को कोई दिक्कत : बघेल

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को दुर्ग रवाना होने से पहले रायपुर के पुलिस ग्राउंड हेलीपैड पर पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दुर्ग दौरे को लेकर उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब दिया। सीएम बघेल ने शाह के दुर्ग में स्वागत की बात कही है। सीएम ने कहा सभी चुनाव प्रचार अपनी पार्टी के लिए करते हैं, यह तो अच्छी बात है करें। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 जून को दुर्ग आ रहे हैं।

छत्तीसगढ़ में भाजपा के सीएम चेहरे को लेकर सीएम बघेल ने कहा कि भाजपा सीएम चेहरा प्रोजेक्ट तो करे, कांग्रेस को भी इंतजार है कि भाजपा से चेहरा कौन है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में थर्ड फ्रंट के सवाल पर सीएम ने कहा कि इससे कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहां दो राष्ट्रीय दल के बीच मुकाबला रहा है।

कांग्रेस सच के साथ है- चुनावी

तैयारियों को लेकर सीएम बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारियां जारी है। सेक्टर और जोन पर प्रशिक्षण शुरू हो गया है। 5 संभागीय सम्मेलन के बाद अब विधानसभा में प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर हम जोर दे रहे हैं। भाजपा सोशल मीडिया पर झूठ फैलाती है। कांग्रेस सच के साथ सोशल मीडिया पर काम करती है।

अजय चंद्राकर पर साधा निशाना- अजय चंद्राकर पर तंज कसते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि उन्हें चुनाव के लिए कोई जिम्मेदारी दी गई है क्या? छत्तीसगढ़ में तो ओम माथुर ही भाजपा के लिए सब कुछ हो गए हैं। माथुर जी हर जगह दिखते हैं, मीडिया, ट्विटर से भाजपा को सफलता नहीं मिलेगी। भाजपा के बड़े नेताओं के दौरे का कोई असर नहीं पड़ेगा।वहीं मणिपुर हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मणिपुर की स्थिति चिंताजनक है। पीएम मोदी और गृहमंत्री शाह, कर्नाटक चुनाव में व्यस्त रहे। बाद में गृहमंत्री 4 दिन तक वहां रहे, फिर भी हालात सामान्य नहीं हो पाया है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। भाजपा के नेता राहुल गांधी के नाम पर एक साथ उठ खड़े होते हैं। छत्तीसगढ़ में बस्तर से सरगुजा तक स्थानीय नेताओं के नाम पर सड़कें और स्मारक हैं। भाजपा को गांधी-नेहरू परिवार से परेशानी है। राहुल गांधी के खिलाफ लाइन से मोदी मंत्रिमंडल के सदस्य खड़े हो जाते हैं। कर्नाटक में नए कानून पर दिया बयान- कर्नाटक में धर्मांतरण कानून में बदलाव के सवाल पर सीएम बघेल ने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। छत्तीसगढ़ में मध्यप्रदेश का जो कानून है वो चल रहा है। रमन सरकार में 2006 में धर्मांतरण पर बिल लाया गया, जो राष्ट्रपति के पास लंबित है। भाजपा ऐसे मुद्दों पर सिर्फ गुमराह करती है। भाजपा को अगर कोई कानून बनाना है तो केंद्र से बना ले और सभी राज्यों में लागू करा लें।छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ महीनों का समय बचा है। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। लगातार नेता एक दूसरे पर तंज कसते नजर आ रहे हैं।

विधानसभा चुनाव में मुकाबला कांग्रेस व भाजपा के बीच ही होगा : मुख्यमंत्री

रायपुर। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया है कि चुनाव में कांग्रेस व भाजपा के बीच ही मुकाबला होगा। तीसरे फ्रंट की कोई गुंजाइश यहां नहीं हैं। भले ही पिछली बार बसपा व जकांछ के गठबंधन ने सात सीट जीत ली थी तब भाजपा ने उन्हे मदद पहुंचायी थी लेकिन अब काफी कुछ बदल चुका है। भाजपा खुद पन्द्रह सीट पर सिमट गई थी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के भारत राष्ट्र समिति में विलय की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया है कि प्रदेश में तीसरे मोर्चे का कोई असर नहीं होने वाला है। राजधानी में मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ऐसे राज्य हैं, जहां राष्ट्रीय दलों की सीधी टक्कर होती है। बहुत लोगों ने कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। पिछले चुनाव में भी भाजपा ने जोगी कांग्रेस की पूरी मदद की, जिसमें जोगी कांग्रेस और बसपा ने मिलकर सात सीट पर जीत दर्ज की। लेकिन उपचुनाव में उनकी ताकत और कम हो गई। दरसअल, छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद से अब तक हुए विधानसभा चुनाव में तीसरे फ्रंट की ओर से पूरी ताकत लगाने के बाद भी सात प्रतिशत से ज्यादा वोट नहीं मिले। पहली बार 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के आलावा जकांछ पांच सीट जीतने में सफल हुई थी। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन के बाद जकांछ कमजोर हुई है और उसके विधायक और वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़कर चले गए हैं। अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव अपनी पार्टी का पड़ोसी राज्यों में विस्तार कर रहे हैं, तो जकांछ के अध्यक्ष अमित जोगी उनकी पार्टी में विलय करने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

संक्षिप्त समाचार

छत्तीसगढ़ में जुटेंगे विहिप के राष्ट्रीय पदाधिकारी, 23 से 26 तक तक होगी चर्चा

रायपुर। छत्तीसगढ़ में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) की केंद्रीय प्रबंध समिति की चार दिवसीय बैठक 23 से 26 जून तक रायपुर के माहेश्वरी भवन में आयोजित की गई है। इस बैठक में 400 से अधिक पदाधिकारियों के शामिल होने की संभावना है। बैठक में मतांतरण सहित हिंदुत्व के तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। इस बैठक में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पूर्व सरकार्यवाह और विहिप के पालक अधिकारी भैयाजी जोशी, विहिप के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. रविंद्र नारायण सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार, महामंत्री मिलिंद परांडे, संगठन महामंत्री विनायक देशपांडे, राम मंदिर निर्माण समिति के महामंत्री चंपत राय समेत राष्ट्रीय पदाधिकारी और 44 संगठन राज्यों के अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और महामंत्री शामिल होंगे।

नेहरु मेमोरियल का नाम बदलना मोदी सरकार की ओछी मानसिकता : वर्मा

भिलाई। पूर्व मेयर उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य

पिछड़ा वर्ग आयोग आर. एन. वर्मा ने देश की राजधानी दिल्ली स्थित मेमोरियल जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू के नाम से था को बदलकर प्रधानमंत्री म्यूजियम एवं लाइब्रेरी सोसायटी करने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि इस प्रकार की कृत्य मोदी सरकार की घटिया हरकत और ओछी मानसिकता का परिचायक है। आर. एन. वर्मा ने आगे कहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का देश की आजादी एवं देश के नवनिर्माण में अमूल्य योगदान रहा है जिसे आधुनिक भारत का शिल्पकार कहा जाता है ऐसे महान शख्सियत का नाम हटाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतंत्र में अलोकांत्रिक परंपरा का शुरुआत किया है जिसे लोकतंत्र में कदापि उचित नहीं कहा जा सकता है। आर.एन. वर्मा ने आगे कहा है कि लोकतंत्र में सत्ता बदलती रहती है मगर हर काल में देश के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति का नाम इतिहास में अमर रहता है। केंद्र सरकार यह गलतफहमी में है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम मेमोरियल से हटा देने से पंडित नेहरू के महत्व को कम कर देंगे। इस प्रकार का कृत्य केवल तानाशाही प्रवृत्ति के लोग ही कर सकते हैं प्रधान मंत्री मोदी को यह भी समझ लेना चाहिए की लोकतंत्र में किसी की भी सरकार स्थाई नहीं होता है।

शिक्षक बनने हजारों ने दिया परीक्षा

रायपुर। शिक्षक बनने के लिए हजारों युवक व युवतियों ने प्री-बीएड और प्री-डीएलएड की परीक्षा दी। प्री. बीएड की परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 12.15 बजे हुई वहीं द्वितीय पाली में 2 से 4.15 बजे प्री-डीएलएड के लिए परीक्षा आयोजित की गई। प्रवेश परीक्षा केंद्र में प्रवेश के पूर्व परीक्षार्थियों को कड़ी जांच के बाद प्रवेश दिया गया। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित प्री. बीएड एवं प्री. डीएलएड प्रवेश परीक्षा शनिवार को अलग-अलग परीक्षा केंद्रों में दो पालियों में संपन्न कराई गई। परीक्षा केंद्रों के बाहर परीक्षार्थियों का सुबह से शाम तक मजमा लगा रहा। पहली पाली की परीक्षा देने के बाद परीक्षार्थिया के चेहरों में मुस्कान साफ झलक रही थी वहीं कुछ परीक्षार्थियों के चेहरे में चिंता की भी लकरी दिखाई दे रही थी।

नवीन संभागायुक्त कार्यालय का भूमिपूजन

रायपुर। छत्तीसगढ गृह निर्माण मंडल अध्यक्ष एवं विधायक श्री कुलदीप सिंह जुनेजा एवं संभागायुक्त डॉ संजय अलंग ने संभागायुक्त कार्यालय परिसर में नवीन कार्यालय भवन का भूमिपूजन किया। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा जानकारी के अनुसार नवीन भवन का निर्माण साढ़े दस हजार वर्गफीट निर्मित होगा। जिसके भूतल में वाहन पार्किंग एवं प्रथम तल में आयुक्त कार्यालय होगा। इसकी लागत करीब 5 करोड़ 53 लाख 56 हजार रूपये है। इस अवसर पर, संयुक्त कमिश्नर श्रीमती सरिता तिवारी, श्रीमती ज्योति सिंह तथा अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

गिरफ्तार सुनील की कोल वाशरी पर ईडी की सील

रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय से आदेश मिलने के बाद कोयला मामले में गिरफ्तार चल रहे कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल की बिलासपुर व कोरबा में संचालित दो कोल वाशरी को ईडी ने शनिवार की दोपहर में सील कर अपने कब्जे में ले लिया। जांच में हुए खुलासा के आधार पर ईडी द्वारा आरोपी बने अधिकारी और कारोबारियों की चल-अचल संपत्ति भी अटैच की गई हैं। ईडी की इसी कार्रवाई में कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल की कोरबा के कोथारी और बिलासपुर में संचालित कोल वाशरी को अटैच किया गया था। इस प्रकरण में ईडी की दिल्ली स्थित निर्णायक प्राधिकारी द्वारा 1 जून को दोनों कोल वाशरी को प्रवर्तन निदेशालय के कब्जे में लेने का आदेश दिया गया। इससे पूर्व इस मामले में ईडी ने पहले ही कोयला कारोबार से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी के बाद उनकी चल अंचल संपत्ति को अटैच कर लिया था। इसके बाद 1 जून को ईडी के दिल्ली स्थित निर्णायक प्राधिकारी से आदेश आने के बाद श्वष्ठ ने कोल वाशरी को अपने कब्जे में लेने की कार्रवाई की गयी हैं। छत्तीसगढ़ में कोल परिवहन पर अवैध लेवी के मामले में पिछले एक साल से प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इस मामले में आईएएस अफसर, कोल कारोबारी सहित कई लोगों को ईडी ने पहले ही गिरफ्तार कर मामले की जांच कर रही हैं।

गर्मी से लोग बेहाल, लू के थपेड़ों ने बढ़ाई परेशानी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी पड़ रही है। चिलचिलाती धूप से लोगों का जीना दूभर हो गया है। लू के थपेड़ों से लोगों की हालत खराब है। राजधानी रायपुर के साथ ही अन्य जिलों में लू चल रहे हैं। मौसम विभाग ने इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कुछ दिनों तक मौसम में कोई बदलाव नहीं होगा। यानी भीषण गर्मी पड़ेगी।

राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में सुबह से ही तेज धूप के साथ गर्मी पड़ रही है। इस भीषण गर्मी से लोगों का दोपहर में घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। दिन में गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। रात को भी गर्म हवा से चैन नहीं मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर-पश्चिम की ओर से आ रही गर्म हवाओं की कारण अगले 2 दिनों तक रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, जांजगीर-चांपा, बलौदाबाजार, बिलासपुर, मुंगेली और महासमुंद जिले के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान जांजगीर-चांपा में 46.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। रायगढ़ में 45.4 डिग्री, बलौदा बाजार में 45.2 डिग्री, मुंगेली में 44.6, बिलासपुर में 43.8, महासमुंद में 43.5, रायपुर में 43.2 डिग्री, दुर्ग में 42.2 डिग्री और राजनांदगांव में 42.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है।

प्रदेश में हीट वेव की देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों के लिए गाइडलाइन जारी किया है। गर्मी से बचने के लोगों को पर्याप्त पानी पीने, प्यास नहीं लगने पर भी पानी पीने की की बात कही गई है। घर में बने शीतल पेय लस्सी, छाछ, नींबू पानी और नारियल पानी जैसे पेय पदार्थों का उपयोग करने की सलाह दिया गया हैं। मौसम विभाग के अनुसार, छत्तीसगढ़ में 19 जून तक लू की संभावना बनी रहेगी। आगामी तीन दिनों तक गर्मी से कोई राहत नहीं मिलने की उम्मीद है। 21 जून तक छत्तीसगढ़ में मानसून बस्तर से शुरू होगा। इसके बाद रायपुर में 24 जून तक पहुंचने की संभावना है।

शिक्षक भर्ती में गेस्ट टीचर को मिलेंगे बोनस नंबर

रायपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अतिथि शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। सरकारी स्कूलों में गेस्ट टीचर के रूप में सेवा देने वालों को बोनस अंक मिलेगा। ऐसे टीचर्स को बोनस के रूप में 2 अंक मिलेंगे। वहीं अधिकतम 10 अंक मिलेंगे। प्रदेश में शिक्षक भर्ती 2023 के अंतर्गत सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता की भर्ती शुरू होने वाली है। इसमें राज्य शासन ने अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने का फैसला लिया है।

शिक्षक भर्ती के लिए 4 मई को विज्ञापन जारी किया गया था। सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता की पदों पर भर्ती शुरू होने वाली है। लोक शिक्षण संचालनालय ने बताया कि अतिथि शिक्षक को 20 जून तक बोनस अंक के लिए अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि निर्धारित समय तक फॉर्म जमा कर दें। तभी बोनस अंक मिलेगा। राज्य शासन के आदेशानुसार, प्रदेश में 12 हजार 489 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी।

लोक शिक्षण संचालनालय ने इस विषय में 12 मई को आदेश जारी किया है। बोनस अंक के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई थी, जिसमें शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षक को प्रत्येक वर्ष के लिए 2 बोनस अंक और अधिकतम 10 अंक देंगे। संचालक लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रमाण पत्र जारी जारी करने का निर्देश दिए हैं। उन्होंने अतिथि शिक्षकों को प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित किए और जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने कहा है। वहीं किसी भी शैक्षणिक सत्र में एक वर्ष से कम अवधि के पढ़ने के लिए कोई अंक नहीं मिलेगा। एक पूर्ण शैक्षणिक सत्र के अध्यापन के लिए 2 अंक मिलेंगे।

भाजपाई शूरवीर नहीं बयानवीर, 7 जन्म में भी नहीं खरीद सकती धान: भगत

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौरा बढ़ता जा रहा है। खाद्यमंत्री अमरजीत भगत शुक्रवार को निजी कार्यक्रम में बिलासपुर पहुंचे थे। यहां मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने धान खरीदी और कई मुद्दों को लेकर भाजपा पर जमकर हमला बोला। अमरजीत ने नारायण चंदेल पर भी निशाना साधा।भाजपा पर कसा तंज- मंत्री अमरजीत भगत ने धान खरीदी को लेकर भाजपा पर कई आरोप लगाए। भगत ने कहा भाजपा इस जन्म में तो क्या 7 जन्मों तक धान नहीं खरीद सकती। भाजपा ना लोगों को पीडीएस में चावल देना चाहती है और ना ही धान खरीदना चाहती है।

मंत्री अमरजीत भगत ने कहा शांता कुमार कमेटी की जो अनुशंसा है, उसमें उन्होंने धान खरीदी का भी एक तरह से विरोध किया है। पीडीएस में जो चावल वितरण किया जा रहा है उसको भी रोकने के लिए अनुशंसा किया है। शांता कुमार भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री रहे हैं, तो यह किससे और क्या बात करेंगे।

भाजपा सिर्फ बयानवीर- भगत ने भाजपा को बयानवीर की उपाधि दे दी। उन्होंने कहा कि बयान देने के मामले में भाजपा सबसे आगे हैं। इस मामले में उनसे एक सिर की मांग करेंगे वो 10 सिर लेकर आएंगे। चाइना भारत के अंदर आकर कई सौ किलोमीटर का कब्जा कर लिया। इसके बाद भी ये शूरवीर बने हुए हैं।

ना बेरोजगारी दूर हुई ना महंगाई कम हुई- खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि भाजपा ने बेरोजगारी दूर करने का वादा किया था। बेरोजगारी तो दूर नहीं हुई उलटे महंगाई कई गुना बढ़ गई। अब ये देश के साधन और धरोहरों को निजी हाथों में देने का काम कर रहे हैं।आरक्षण विधेयक पास कराए भाजपा- भगत ने आरक्षण विधेयक राज्यपाल के पास लंबित होने के मामले में भी भाजपा की टांग खीचीं। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों में थोड़ी भी शर्म, है तो राज्यपाल से बोलकर उसमें दस्तखत कराएं, तभी आगे ये फील्ड में निकलने लायक रहेंगे, नहीं तो यह मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आरक्षण विधानसभा में पारित करके राज्यपाल के पास भेजा गया है लेकिन कुछ लोग इसमें दस्तखत करने नहीं दे रहे हैं। जल्द इनका चेहरा बेनकाब होने वाला है।

नेहरू संग्रहालय का नाम बदलना मोदी सरकार की संकुचित मानसिकता : मरकाम

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल के नाम पर बने नेहरू संग्रहालय के नाम को बदले जाने को कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी और भाजपा की संकुचित मानसिकता बताया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि संकीर्णता और प्रतिशोध का दूसरा नाम नरेंद्र मोदी है। 59 वर्षों से अधिक समय से नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय दुनिया भर के विद्वानों के लिये जिज्ञासा शांत करने का केंद्र रहा है। मोदी सरकार ने इसका नाम बदलकर अपनी छोटी सोच को प्रदर्शित किया है। भाजपा कहां-कहां से महात्मा गांधी और पं. जवाहर लाल नेहरू के नाम को हटायेगी। नेहरू का नाम जो देश के जन मन में रचा बसा है। इस देश की आजादी से लेकर आधुनिक भारत के नव निर्माण में पं. जवाहर लाल नेहरू का अतुल्य

योगदान है। आजादी का लड़ाई में अपनी जवानी के 16 साल से अधिक समय को पं. नेहरू ने अंग्रेजों की जेलों में बिताया था। उन्होंने कभी भाजपा आरएसएस के पितृ पुरूषों की भांति न अंग्रेजों की चाटुकारिता किया था और न ही जेल से रिहाई के लिये सावरकर के जैसे अंग्रेजों के सामने माफी नामा दिया था।

मरकाम ने कहा कि भाजपा और मोदी दुर्भावनावश पं. जवाहर लाल नेहरू के नाम से बने संग्रहालय का नाम भले ही बदल ले लेकिन पं. नेहरू द्वारा बनाये गये भाखड़ा नांगल बांध सिंचाई परियोजनाये बोकारो, राउर केला, दुर्गापुर, भिलाई जैसे उद्योगो पर से नेहरू जी की छाप कैसे मिटायेंगे? जब भाजपा के पूर्वज श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पं. दीनदयाल उपाध्याय, अपने दल के राजनैतिक वजूद की तलाश के लिये देश में हिन्दू मुस्लिम और क्षेत्रवाद का जहर बो कर सांप्रदायिकता फैलाकर विघटन फैलाने की कोशिशे में लगे हुये थे तब पं. जवाहर लाल नेहरू भारत में शिक्षा व्यवस्था का प्रचार प्रसार, स्कूल कालेजो का निर्माण, मेडिकल कालेजो का निर्माण, एम्स आईआईएम आईआईटी बना रहे थे। देश के नव निर्माण के लिये सुई से लेकर हवाई जहाज बनाने की योजनायें बना कर क्रियान्वयन करवा रहे थे। उन्होंने कहा कि यदि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश के सभी प्रधानमंत्रियों की यादों को सहेजने स्मारक बनाने की योजना बना रहे है उसका स्वागत है। लेकिन देश के प्रथम प्रधानमंत्री महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पं. जवाहर लाल नेहरू के नाम से बने स्मारक को बदलना मोदी का नेहरू जी के प्रति पूर्वाग्रह को दर्शाता है।

राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में एक साथ दिखे बृजमोहन, महंत, लखमा

रायपुर। मुंबई के सबसे पॉश इलाका बीकेसी में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन (एनएलसी भारत) में छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और बीजेपी के विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने शिरकत की। यहां देशभर के विधायकों का मार्गदर्शन करने पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। उनसे विभिन्न संवैधानिक विषयों पर सार्थक चर्चा की।

इस दौरान छत्तीसगढ़ के विधायकों ने प्रदेश की पवित्र पवित्र मिट्टी और महानदी का जल देश के नाम समर्पित किया। विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि मुंबई में आयोजित हो रहे इस तीन दिवसीय राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में छत्तीसगढ़ सहित समूचे भारत के समस्त राज्यों के 2800 विधायक शामिल हुए हैं। सम्मेलन में लोकतंत्र में नीति निर्माण विधायिका को मजबूती सदन में विधायकों की भूमिका और कार्यभार जैसे विषयों पर मंथन हो रहा है। साथ ही भारत की एकता और अखंडता को और मजबूत बनाए रखने के लिए दलगत भाव, क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद से

ऊपर उठकर राष्ट्रवाद को बल देने का प्रयास भी हो रहा है। इसके तहत एक भारत-श्रेष्ठ भारत निर्माण की भावना के साथ देशभर के विधायकों से साथ में मिट्टी और नदी का जल लाने का आग्रह किया गया था। यहा पहुंचे छत्तीसगढ़ के विधायकों ने भी अपने राज्य की पवित्र मिट्टी और महानदी का जल मां भारती के नाम पर समर्पित किया। इस मौके पर प्रदेश की विधानसभा में एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने वाले बीजेपी-कांग्रेस के विधायक मुंबई में एक साथ हंसते-मुस्कुराते दिखें। बृजमोहन अग्रवाल और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत एक साथ नजर आए। कवासी लखमा भी इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे।

अधूरे वेतन समझौते को पूर्ण करने एवं ठेका मजदूरों की मांगों पर सीटू का महाधरना

दल्लीराजहरा। स्टील वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (सीटू) के आह्वान पर सेल कर्मियों की वेज रिवीजन एवं लंबित मांगों को लेकर आज स्थानीय हिंदुस्तान स्टील एंप्लाइज यूनियन सीटू राजहरा के नेतृत्व में खदान कर्मचारियों ने माइंस ऑफिस के समक्ष विशाल महाधरना किया। उल्लेखनीय है कि सेल के नियमित कर्मचारियों के आधे अधूरे वेतन समझौते और ठेका मजदूरों की वेतन बढ़ोतरी पर प्रबंधन के नकारात्मक रवैए के खिलाफखदान सहित पूरे सेल के कर्मचारी बेहद आक्रोशित है। सेल की तमाम इकाइयों में बिगत एक वर्ष से अलग-अलग प्रकार से धरना प्रदर्शन के माध्यम से यह प्रयास किया गया कि प्रबंधन जल्द से जल्द एनजेसीएस की बैठक बुलाकर लंबित मुद्दों का निराकरण करे, लेकिन सेल प्रबंधन अपने अड़ियल रवैया पर डटा हुआ है । लगभग एक वर्ष से इन मुद्दों पर कोई पहल प्रबंधन की ओर से नहीं की जा रही है। प्रबंधन के इस रवैया से क्षुब्ध, स्टील वर्कर्स फेडरेशन आफ इंडिया (सीटू) ने अब ठान लिया है कि सेल में सिलसिलेवार संघर्ष को तेज करते हुए प्रबंधन से आर-पार की लड़ाई करनी होगी । इसी रणनीति के तहत पूरे

सेल में 15 और 16 जून को विशाल धरना कर प्रबंधन को आगाह किए जाने का कार्यक्रम किया जा रहा है । दल्ली राजहरा में आयोजित खदान कर्मियों के धरने को संबोधित करते हुए यूनियन के सचिव प्रकाश क्षत्रिय ने कहा कि सेल प्रबंधन का रवैया न केवल नकारात्मक है बल्कि श्रमिक विरोधी भी है। प्रबंधन लगातार किसी न किसी बहाने सेल कर्मचारियों को मिली हुई सुविधाओं और लाभों में एकतरफा ढंग से कटौती करने के आदेश जारी करते जा रहा है। ग्रेज्युटी सीलिंग का आदेश इसका ज्वलंत उदाहरण है। उन्होंने कहा कि सेल में पहली बार ऐसा हुआ है जब बहुमत यूनियनों के हस्ताक्षर से सेल कर्मियों पर एक नुकसानदेह,और अधूरा वेतन समझौता लाद दिया गया। बेहद कम एमजीबी पर 10 साल के लिए किया गया वेतन समझौता किसी भी कीमत पर कर्मचारियों के हित में नहीं है। इस समझौते में 39 माह के एरियर्स के संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किए जाने के कारण सेल के कर्मचारी एरियर्स से आज तक वंचित है । इसी तरह नाइट शिफ्ट एलाउंस एचआरए एवं अन्य भत्तों पर मात्र कमेटी बनाकर छोड़ दिया गया है ,जिन कमेटियों की बैठक तक नहीं हो रही है। आक्रोशितकर्मचारी अपना गुस्सा सोशल मीडिया पर उतार रहे हैं लेकिन समस्या का समाधान संघर्ष के बिना नहीं निकलने वाला है। उन्होंने कहा कि बहुमत के आधार पर समझौते पर हस्ताक्षर करने वाली यूनियने अब ना तो प्रबंधन से कुछ करवा पा रही है और ना ही संघर्ष के मैदान में उतरने को तैयार है। निश्चित रूप से यह रवैया किसी गुप्त समझौते की ओर इशारा करता है। एनजेसीएस ने बहुमत की परिपाटी सेल कर्मचारियों को बहुत ही खतरनाक स्थिति में ले जाने वाली है। बोनस के मुद्दे पर भी बहुमत के आधार पर जो फार्मूला तय किया गया उससे कर्मचारियों को नुकसान होना तय है। कर्मचारियों को ट्रेड यूनियनों का चरित्र पहचान कर संघर्षरत संगठन के साथ खडा होना होगा तभी इस तानाशाह प्रबंधन से हम अपने अधिकारों को बचा पायेंगे।

यूनियन के अध्यक्ष पुरषोत्तम सिमैया ने कहा कि कर्मचारियों को नुकसान पहुंचाकर चुप्पी साधे यूनियनों से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है।खदान की भी कुछ यूनियनों ने खदान कर्मचारियों का दासा 10व की जगह 8व करवा दिया।जिसके खिलाफ सीटू आज भी संघर्षरत है।हमें नये बेसिक पर 10व दासा हर हाल में चाहिए। यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र सिंह ने कहा कि सेल के ठेका मजदूरों के साथ प्रबंधन व बहुमत यूनियनों ने बहुत बडी धोखाधड़ी की है। 30 जून का हडताल में यूनियनों ने वादा किया था कि नियमित व ठेका कर्मचारियों का वेतन समझौता एक साथ किया जायेगा लेकिन अक्टूबर में ठेका मजदूरों को दरकिनार कर एक आधा अधूरा समझौता कर लिया गया। ठेका मजदूरों को मात्र कमेटी का लालीपॉप ही मिल पाया।

क्यों सफाई देनी पड़ रही है टी एस सिंहदेव को ?

छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव समय-समय पर बयान देकर राजनीति को गरमाते रहते हैं। आजकल उनके कांग्रेस छोड़कर कहीं न जाने की बात चर्चा में हैं।

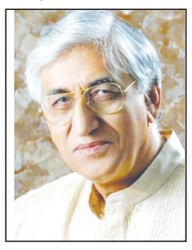

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनकी दूरी कई बार सार्वजनिक हो चुकी है। 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले भूपेश बघेल और टी एस सिंहदेव की जोड़ी को जय-वीरू की जोड़ी के रूप में देखा जाता रहा है। सत्ता में आने के बाद दोनों के संबंधों में दरार नजर आई। टी एस सिंहदेव ने अपनी उपेक्षा से दुखी होकर एक विभाग छोड़ भी दिया। अब दोनों ने गले मिलकर जय-वीरू वाली छवि जनता के सामने पेश की। गले से ज्यादा जरुरी है दिल मिलना। टी एस सिंहदेव के स्वास्थ्य विभाग में अफसरों में हेरफेर को एक रिकार्ड माना जा रहा है। साढ़े चार साल में स्वास्थ्य विभाग में 4-5 प्रमुख सचिव और सचिव बदल चुके हैं। यही हाल जीएसटी कमिश्नर और स्वास्थ्य संचालक का भी है। अभी टी एस सिंहदेव के साथ आस्ट्रेलिया दौरे पर गए स्वास्थ्य सचिव प्रसन्ना आर और स्वास्थ्य संचालक के पद से भीमसिंह का तबादला चर्चा में हैं। टी एस सिंहदेव का परिवार पूरी तरह से कांग्रेसी है। सिंहदेव की माताजी देवेंद्र कुमारी सिंहदेव संयुक्त मध्यप्रदेश में मंत्री थीं, उनके पिता एम एस सिंहदेव मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव रहे, फिर दिग्विजय सिंह के

रवि भोई

कार्यकाल में राज्य योजना मंडल के उपाध्यक्ष रहे। बहन भी हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस की विधायक रहीं। मध्यप्रदेश में एम एस सिंहदेव को दिग्विजय सिंह का सलाहकार माना जाता था। कट्टर कांग्रेसी होने के बाद भी टी एस सिंहदेव के कांग्रेस में बने रहने की बात करना लोगों के गले उतर नहीं रही है। कहा जा रहा है कि टी एस सिंहदेव के मन में कुछ तो मलाल है, इस कारण मौका मिलते ही कांग्रेसी होने का राग आलाप देते हैं।

आईएएस अफसरों में धुकधुकी

कहते हैं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में एडिशनल सीईओ और ज्वाइंट सीईओ के नाम पर कुछ आईएएस अफसरों का दिल धुक-धुक करने लगा है। अब तक एडिशनल सीईओ रहीं शिखा राजपूत तिवारी को सरगुजा संभाग का आयुक्त बना दिया गया है। कहा जा रहा है कि एडिशनल सीईओ के लिए 2007 से 2012 बैच के 7 अफसरों का नाम मुख्यमंत्री को भेजा गया है। इसके बाद तीन नामों का पैनल भारत निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। 2023 का विधानसभा चुनाव का बोझ किस अफसर पर आन पड़ता है, इसको लेकर 2007 से 2012 बैच के अफसर सकते में हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में दो ज्वाइंट सीईओ भी बनाए जाने हैं। अब ज्वाइंट सीईओ आईएएस होते हैं या सीनियर डिप्टी कलेक्टर, इसको लेकर भी कयासबाजी चल रही है।

चलते रहेंगे अशोक जुनेजा

डीजीपी अशोक जुनेजा भले 30 जून को 60 साल के हो जाएंगे, पर अगस्त तक तो वे पद पर बने रहेंगे। 1989 बैच के आईपीएस

जुनेजा 11 नवंबर 2021 को डीजीपी बनाए गए थे, लेकिन संघ लोकसेवा आयोग ने डीजीपी के पद पर उनका कन्फर्मेशन अगस्त 2022 में किया था। ऐसे में उनकी नियुक्ति की तारीख अगस्त से और यूपीएससी के कन्फर्मेशन के बाद डीजीपी के पद पर दो साल की गणना की जा रही है। अगस्त के बाद उनके एक्टेंशन के लिए केंद्र से अनुमति लेनी पड़ेगी। राज्य में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं , ऐसे में 2023 में चुनाव के वक्त अशोक जुनेजा ही डीजीपी रहेंगे या कोई और के पास कमान होगी, इसके लिए इंतजार करना होगा। अशोक जुनेजा के बाद 1990 बैच के आईपीएस राजेश मिश्रा वरिष्ठता क्रम में हैं। राजेश मिश्रा जनवरी 2024 में रिटायर होंगे। कहते हैं कुछ लोग राजेश मिश्रा को डीजीपी बनाने के पक्ष में हैं। किस्मत साथ दे दे तो कुछ महीनों के लिए राजेश मिश्रा की लाटरी लग सकती है।

जमीन तैयार करने में लगे हैं अरुण साव

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव अपनी जमीन तैयार करने में जी-जान से लग गए हैं। कहते हैं आरएसएस की पृष्ठभमि वाले

अरुण साव को हाईकमान का वरदहस्त मिल गया है। इस कारण अरुण साव जनता और कार्यकर्ता दोनों से प्रगाढ़ता बढ़ाने और उनके दु:ख दर्द जानने व समझने में लगे हैं। छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओमप्रकाश माथुर के 10 से 14 जून तक के कार्यक्रम में भी अरुण साव की सक्रियता चर्चा में है। ओमप्रकाश माथुर 10 से 14 जून के बीच पांच दिनों में जमीन पर उतरकर भोजन और चर्चा के बहाने पार्टी जनों व आम लोगों से मिले। राजिम से लेकर मोहला मानपुर जैसे इलाकों में ओमप्रकाश माथुर जैसे दिग्गज नेता के धूल उड़ाने का फायदा 2023 के विधानसभा चुनाव में कितना मिलता है, यह तो समय ही बताएगा ? पर दिल्ली से आकर ओ पी माथुर के जिला, तहसील और ब्लाक मुख्यालय में पहुँचने से उन्हें पार्टी की जमीनी हकीकत का अंदाजा भी होगा ही, साथ में निचले स्तर के कार्यकर्ताओं में जोश भी जगेगा।

आईएफएस साहू और राव का प्रमोशन इसी माह ?

कहते हैं पीसीसीएफ बने बिना पीसीसीएफ की कुर्सी पर विराजे वी श्रीनिवास राव को पदोन्नत करने के लिए इस महीने डीपीसी हो जाएगी। 1988 बैच के आईएफएस आशीष कुमार भट्ट इस महीने रिटायर हो जाएंगे। कहा जा रहा है कि उनके रिटायरमेंट की प्रत्याशा में डीपीसी हो जाएगी, फिर 1990

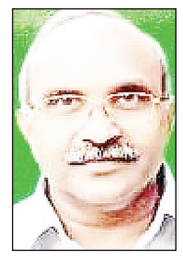

बैच के आईएफएस वी श्रीनिवास राव के नाम के आगे से एपीसीसीएफ का तगमा हट जाएगा और वे पूर्णकालिक पीसीसीएफ हो जाएंगे। 1990 बैच में वी श्रीनिवास राव से वरिष्ठता क्रम में अनिल साहू ऊपर हैं। अनिल साहू अभी छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के प्रबंध संचालक हैं। ऐसे में अनिल साहू भी पीसीसीएफ बन जाएंगे। कहा जा रहा है फिलहाल वे विभाग में नहीं आ पाएंगे। पर्यटन मंडल में रहेंगे, पर वेतन-भत्ते का लाभ मिल जाएगा। रायपुर के सीएफ जे आर नायक भी इस महीने रिटायर हो रहे हैं। कई सीएफ - डीएफओ भी एक जगह तीन साल से जमे हैं। माना जा रहा है कि वन विभाग में इस महीने सीएफ और डीएफओ की लंबी लिस्ट निकल सकती है।

चावल गड़बड़ी में घुसी ईडी

कहते हैं ईडी कोयला और शराब के बाद अब चावल गड़बड़ी में घुस गई है। खबर है कि पिछले दिनों पांच राइस मिलरों को नोटिस जारी कर तलब किया है। चावल घोटाले में एक कांग्रेस नेता पर गाज गिरने का संकेत है। ये नेता चावल के पुराने खिलाड़ी हैं। चावल मामले में 26 करोड़ के एफडी की बड़ी चर्चा है। कहा जा रहा है कि अब ईडी कोर्ट-कचहरी के चक्कर में है। इसके अलावा ईडी दस्तावेजी सबूत जुटाने में लगी है। माना जा रहा है कि ईडी जून के आखिरी हफ्ते या जुलाई के पहले हफ्ते में एक्शन में आएगी।

आईएएस सारांश मित्तर पर भारी बोझ

2010 बैच के आईएएस सारांश मित्तर पर भूपेश सरकार ने खूब भरोसा जताया है और उन्हें मंत्रालय में संयुक्त सचिव उद्योग के साथ

दो निगम का प्रबंध संचालक व दो विभाग का संचालक बनाया है। सरकार के भरोसे पर कितने खरे उतारते हैं, यह समय बताएगा ? पांच जिम्मेदारियों का किस तरह निर्वहन करते हैं, यह भी देखना होगा ? डॉ. मित्तर को प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ रोड़ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट कार्पोरेशन, प्रबंध संचालक सीएसआईडीसी के साथ संचालक नगरीय प्रशासन व विकास एवं संचालक उद्योग की जिम्मेदारी दी गई है। सीएसआईडीसी और उद्योग संचालनालय सीधे जनता से जुड़े महकमे हैं।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार और पत्रिका समवेत सृजन के प्रबंध संपादक हैं।)

सरकार अवैध कारोबार को संरक्षण देकर भ्रष्टाचार के नए-नए प्लॉट बना रहे : साव

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरूण साव ने कहा है कि पूर्ण शराबबंदी के अपने वादे से मुकर चुकी प्रदेश की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब नशाबंदी के नाम पर सियासी लफ्फाजी करने में लगे हैं। श्री साव ने कहा कि शराब व मादक पदार्थों की तस्करी और उसके जरिए घोटालों को संस्थागत रूप देने के लिए मुख्यमंत्री बघेल अब नशाबंदी की बातें करके इस पूरे अवैध कारोबार को संरक्षण देकर भ्रष्टाचार के नए-नए प्लॉट बना रहे हैं। लेकिन प्रदेश का यह सौभाग्य है कि प्रदेश की जागरूक जनता अब कांग्रेस की इस झूठी सरकार को दुबारा सत्ता नहीं सौंपेगी और छत्तीसगढ़ की रक्षा के लिए आगे आएगी।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साव ने कहा कि शराबबंदी का

वादा करके कांग्रेस की भूपेश सरकार ने दो हजार करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। अब मुख्यमंत्री बघेल और कांग्रेस के लोग बाताएं कि नशाबंदी की बातें करके वे कितने हजार करोड़ रुपयों का संस्थागत घोटाला करने की मंशा पाले बैठे हैं? कांग्रेस की सरकार ने पिछले साढ़े चार वर्षों में हर मोर्चे पर अपने घोटालों व भ्रष्टाचार के राजनीतिक चरित्र का परिचय दिया है। गौठान घोटाला, गोबर घोटाला, वर्मी कम्पोस्ट घोटाला इसकी तस्दीक कर रहे हैं। धान तस्करी, रेत चोरी, शराब घोटाला, नशे के व्यापार जैसे अवांछनीय कृत्यों के जरिए प्रदेश में युवाओं को बर्बाद करने का जो स्टार्ट-अप शुरू हुआ है, प्रदेश कांग्रेस को तो अब अपने कार्यकर्ताओं को इसका प्रशिक्षण भी ज़रूर देना चाहिए।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ को शराब, ड्रग्स, गांजा, अफीम, हेरोइन आदि की तस्करी को अपरोक्ष-अपरोक्ष संरक्षण देकर प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ महतारी की गरिमा और मान-सम्मान को तहस-नहस करके रख दिया है। राजधानी रायपुर तो ड्रग्स माफिया नेटवर्क के लिए सेंटर पॉइंट बन गया है जहाँ पंजाब महाराष्ट्र, ओड़िशा से सूखे नशीले पदार्थों को बेखौफ और बेरोकटोक तस्करी कर खपाया जा रहा है। इसके कारण प्रदेश में अपराधों का ग्राफ बढ़ा है।

जिला अस्पताल में रात में भी सिजेरियन प्रसव की सुविधा, विशेषज्ञ डॉक्टर भी रहे तैनात

रायपुर। रायपुर के जिला अस्पताल में रात में भी किसी गर्भवती महिला को आवश्यकता पड़ने पर अब ऑपरेशन की सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे ने आज जिला अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की आवश्यकता पड़ने पर रात में भी ऑपरेशन कर प्रसव कराने की सुविधा शुरू करने के निर्देश सिविल सर्जन को दिए है। उन्होंने इसके लिए ऑपरेशन थियेटर को तैयार रखने के साथ प्रशिक्षित स्वास्थ्य अमले और विशेषज्ञ डॉक्टर की भी तैनाती करने को कहा है। कलेक्टर ने यह निर्देश आज स्वास्थ्य विभाग के कामकाज की समीक्षा बैठक में दिए।

बैठक में कलेक्टर ने सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में संस्थागत प्रसव बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं की पहचान कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं-मितानिनों के माध्यम से उनकी समय-समय पर स्वास्थ्य जांच और सोनोग्राफी आदि कराने के भी निर्देश दिए। कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रॉस मीटिंग हॉल में हुई बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अबिनाश मिश्रा, नगर निगम आयुक्त श्री मयंक चतुर्वेदी, सहायक कलेक्टर श्री जयंत नहटा, सीएमएचओ डॉ. मिथलेश चैधरी सहित सभी खण्ड चिकित्सा अधिकारी, शासकीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के नोडल अधिकारी तथा जिला कार्यक्रम प्रबंधक भी मौजूद रहें बैठक में डॉ. भुरे ने जिले के स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत और शुरू हो चुके अधोसंरचना निर्माण संबंधी सभी कामों को समय-सीमा निर्धारित कर गुणवत्ता पूर्वक पूरा करने के निर्देश दिए।

कांगेर घाटी को वैश्विक धरोहर स्थल के रूप में विकसित करने की संभावनाओं पर कार्यशाला

■ कांगेर घाटी के गुफाओं की विविधता तथा उनकी अनूठी संरचना पर हुई चर्चा

रायपुर। बस्तर के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की जैव विविधता धरोहर, प्राकृतिक सुंदरता एवं बस्तर की संस्कृति को समेटे राष्ट्रीय उद्यान को वैश्विक मानचित्र पर स्थापित किए जाने हेतु कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान द्वारा विगत दिवस कार्यशाला का आयोजन किया गया। पार्क के डायरेक्टर श्री धम्मशील गणवीर द्वारा बताया गया कि कार्यशाला में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के वैश्विक विरासत नामांकन के लिए कई अहम पहलुओं पर चर्चा की गई। वैश्विक विरासत हेतु कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के नामांकन के लिए विशेषज्ञ द्वारा अनेक मानदंड बताए गए एवं ओयूवी निर्धारण के विषय पर चर्चा की गई। साथ ही कांगेर घाटी के लिविंग हेरिटेज पर भी चर्चा की गई। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के गुफाओं की विविधता तथा उनकी अनूठी संरचना से पृथ्वी के इतिहास का अध्ययन पर विचार रखे गए। वहीं राष्ट्रीय उद्यान के अनोखे जैव विविधता पर भी जूलॉजिकल सर्वे ऑफइंडिया के विशेषज्ञ द्वारा चर्चा की गई। राष्ट्रीय उद्यान के वनौषधियों एवं उनके महत्व पर भी चर्चा हुई। एंथ्रोपोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के

विशेषज्ञ द्वारा राष्ट्रीय उद्यान की प्राकृतिक विविधता का सांस्कृतिक विरासत से मेल पर भी प्रकाश डाला गया। कार्यशाला में प्रोफेसर एम एल नायक, रिटायर्ड प्रोफेसर एवं एचओडी, लाइफ साइंस, पंडित रवि शंकर विश्वविद्यालय, रायपुर, डॉ भूमेश भदौरिया, टेक्निकल ऑफिसर, वाइल्डलाइफइंस्टीटूट ऑफइंडिया, डॉ जयंत विस्वास, डायरेक्टर, नेशनल केव रिसर्च व प्रोटेक्शन, प्रत्युष महापात्रा, साइंटिस्ट, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अमितांशु झा, एचओडी, जियोलॉजी, काकतीय विश्वविद्यालय, मोहम्मद नाहर, फैकल्टी, आईआईटीएम, भुवनेश्वर, पर्यटन विशेषज्ञ आदि शामिल थे।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

भाजपा के तमाम हथकंडे नाकाम रहे : मरकाम

रायपुर। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह के प्रस्तावित दौरों पर तंज कसते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि 15 साल के रमन राज के कुशासन के बाद 14 सीट में सिमट चुके भारतीय जनता पार्टी की स्थिति छत्तीसगढ़ में दिनोंदिन कमजोर होती जा रही है। भाजपा के तमाम हथकंडे छत्तीसगढ़ में

नाकाम रहे। 2018 के चुनाव के दौरान धरमलाल कौशिक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे उसके बाद विक्रम उसेंडी फिर विष्णुदेव साय और अब भाजपा के सबसे निष्क्रिय सांसद अरुण साव को अध्यक्ष बनाए जाने से भाजपा कार्यकर्ताओ में घोर निराशा है। अरुण साव को बिलासपुर की जनता ने सांसद के रूप में चुना है। बिलासपुर जोन देशभर में सर्वाधिक कमाई करके देने वाला रेलवे जोन है, केवल माल भाड़े से 22,000 करोड़ से अधिक की आय केंद्र की मोदी सरकार को होती है लेकिन सुविधा के नाम पर केवल छलावा, हर महिने सैकड़ों ट्रेनें अचानक रद्द कर दी जा रही है, बिलासपुर से शुरू की गई हवाई सेवा भी अचानक रद्द कर दी गई इस पर भी सांसद अरुण साव मौन रहे। विगत साढ़े चार वर्षों में भाजपा के आधा दर्जन नए प्रभारी आ गए, 2018 में विधानसभा चुनाव के समय सौदान सिंह छत्तीसगढ़ में भाजपा के प्रभारी हुआ करते थे फिर डी पुरंदेश्वरी आई, नितिन नवीन, शिव प्रकाश, अजय जामवाल, ओम माथुर लाए गए।

मोदी सरकार की अर्थनीति चंद पूंजीपतियों के मुनाफे पर : वर्मा

रायपुर। थोक और खुदरा महंगाई दर के संदर्भ में जारी आंकड़ों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां केवल चंद पूंजीपति मित्रों के हितों पर फोकस है। एक तरफ जहां होलसेल प्राइस इंडेक्स -3.4 प्रतिशत है। अर्थात उत्पादक और किसानों के द्वारा जो सामग्री थोक

विक्रेताओं/ वितरकों को बेचे जाते हैं वहां पर बेहद कम कीमत दी जा रही है। दूसरी ओर खुदरा विक्रय अर्थात दुकानदारों द्वारा जो ग्राहकों को बेचा जाता है, वहां पर महंगाई दर 4.25 प्रतिशत है। तात्पर्य यह है कि न उत्पादक किसानों को लाभ मिल रहा है, और न ही अंतिम उपभोक्ता आम जनता को कोई फायदा है। पूरा का पूरा लाभ बड़े होलसेलर कारोबारियों को ही मिल रहा है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार सब्जियों में थोक मूल्य सूचकांक -30.1 प्रतिशत है। आलू का थोक मूल्य सूचकांक -18.2 प्रतिशत, आयल सीड - 15.6 प्रतिशत और वनस्पति घी - 29.5 प्रतिशत है लेकिन इन्हीं सामग्रियों का खुदरा मूल्य सूचकांक 3.29 प्रतिशत है। अर्थात उत्पादक किसानों पर एक तरह से कृत्रिम राष्ट्रीय आपदा मोदी सरकार के संरक्षण में लाई गई है। किसानों से खरीदी में लगभग एक तिहाई तक दाम में कटौती कर दी गई है, लेकिन खुदरा विक्रय की दरें लगभग 4.25 प्रतिशत अधिक है। मोदी सरकार की नीतियां किसानों को लूटने, आम उपभोक्ताओं से खींचने और पूंजीपतियों को सिंचने की है।

सीमित अवधि के लिए खोलें पीएम फसल बीमा योजना पोर्टलः डॉ. रमन

रायपुर। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को पत्र लिखा है। खत में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल को खोलने के लिए अनुरोध किया है। उन्होंने सीमित

अवधि के लिए पोर्टल को खोलकर विगत वर्षों के बीमित कृषकों के बीमा रिकार्ड में सुधार करने का आग्रह किया है। ताकि राजनांदगांव जिले के वंचित किसानों को केंद्र की इस जनहितकारी योजना का लाभ मिल सके।

इसके पूर्व केंद्र सरकार की ओर से कृषि उत्पादों का समर्थन मूल्य बढ़ाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया था। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों के हित में ऐसा फैसला भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हुआ है। मोदी सरकार में हर वर्ष समर्थन मूल्य की वृद्धि हुई जबकि केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तो कभी उन्हें एमएसपी बढ़ाना याद नहीं आया। उन्होंने केंद्र सरकार के बढ़ाए गए समर्थन मूल्य और छत्तीसगढ़ शासन के समर्थन मूल्यों पर चर्चा करते हुए कहा कि जिस धान का समर्थन मूल्य 1360 रुपए था, वो अभी बढ़ाकर 2183 हो गया है।

रमन सिंह अपनी राजनैतिक फसल की चिंता में केंद्र को पत्र लिख रहे : सुशील

रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में केंद्रीय कृषि मंत्री को लिखा गया पत्र रमन का घड़ियाली आंसू है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग

के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि रमन सिंह किसानों के हित में फसल बीमा की चिंता नहीं कर रहे अपनी चुनावी फसल की चिंता सता रही है यह समस्या केवल राजनांदगांव या छत्तीसगढ़ की नहीं पूरे देश की है। फसल बीमा की विसंगति के बारे में राज्य सरकार लगातार केंद्र का ध्यानाकर्षण करती रही है लेकिन मोदी सरकार इस दिशा में उदासीन बनी हुई। छत्तीसगढ़ से भाजपा के 9 सांसद है किसी ने भी फसल बीमा के संबंध में किसानों की समस्या की आवाज नहीं उठाया है।प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा लालकिले से बोला गया सबसे बड़े झूठों में से एक प्रधानमंत्री फसल बीमा भी है। प्रधानमंत्री ने वायदा किया था कि यह व्यक्तिगत ईकाई के रूप में लागू की जायेगी लेकिन शुरूआत से ही व्यक्तिगत की बजाय सामूहिक रहा।

नशा मुक्ति अभियान को लेकर भाजपा नेता विचलित : वंदना

रायपुर। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि नशा मुक्ति अभियान को लेकर भाजपा के नेता विचलित है जब-जब भूपेश बघेल की सरकार ने छत्तीसगढ़ को नशा से मुक्त के लिए सकारात्मक पहल किए हैं विपक्ष में बैठे भाजपा के नेताओं के मुंह जब भी खुली नकारात्मक ही

बात कहें हैं। भाजपाई कभी नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ नशे से मुक्त हो।पूर्ववर्ती भाजपा सरकार डॉक्टर रमन सिंह की नाक के नीचे हुक्का बार और नशे का कारोबार धड़ल्ले से चलता था। भूपेश बघेल के सरकार में हुक्का बार पर कार्यवाही करते हुए हुक्का बार को बंद कर दिया गया। भाजपा के नेता कमीशन कमाने के चक्कर में शराब के सरकारी करण किया और स्वयं सरकार शराब बेच करके 4400 करोड़ शराब घोटाला किया गया। बेटियों और बच्चियों को होटल में शराब परोसने का ट्रेनिंग भाजपा के सरकार में दिया जाता था। 15 साल तक छत्तीसगढ़ को नशे के गर्त में धकेलने का काम किया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कभी भी यह विचार सामने नहीं आया कि शराबबंदी या नशा मुक्ति के लिए काम करेंगे। गुजरात ड्रग्स का सेंटर बन गया है और सारे ड्रग्स मुंद्रा पोर्ट से निकल रहे हैं लेकिन भाजपा के सरकार कोई कार्यवाही नहीं करती। हर दो-तीन महीने में मुंद्रा पोर्ट में ड्रग्स मिलते हैं जो भारत के युवाओं के भविष्य को नष्ट कर रहे हैं।

भाजपा ने एमपी-छत्तीसगढ़ में झोंकी पूरी ताकत

■ मोदी, शाह और नड्डा के चुनावी राज्यों में होंगे तूफानी दौरे

रायपुर। छत्तीसगढ़ में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे लेकर भाजपा और कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। विपक्षी दल भाजपा के बड़े नेता अब प्रदेश में प्रचार करते नजर आएंगे। एक जुलाई को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। राजनाथ सिंह नक्सल प्रभावित जिले कांकेर में पार्टी के नेताओं से मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए आम सभा को भी संबोधित कर सकते हैं। इनके अलावा अमित शाह और जेपी नड्डा भी इसी महीने छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दुर्ग दौरा प्रस्तावित है। पीएम मोदी सात अगस्त को दुर्ग जिले

का दौरा कर सकते हैं। जहां छत्तीसगढ़ के पहले आईआईटी का लोकार्पण भी किया जा सकता है।

मिली जानकारी के अनुसार, भाजपा इन दिनों पूरे प्रदेश में महा-जनसंपर्क अभियान चला रही है। पार्टी केंद्र के बेहतर कामों का पूरी ताकत से प्रचार प्रसार करती नजर आ रही है। आने वाले दो महीने में पार्टी हर जिले में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करेगी। इन कार्यक्रमों के लिए स्थानीय नेताओं को जिम्मेदारी सौंप दी है। फिलहाल केंद्र सरकार के नौ साल पूरे होने पर प्रदेश भर में अलग-अलग जगहों पर बैठकें, सभाएं चल रही हैं।

जानकारी के अनुसार, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 22 जून को भिलाई आएंगे। उनके स्वागत को लेकर भाजपा की तैयारियां जोरों पर हैं। अमित शाह की सभा में 50,000 कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसके लिए 20 विधानसभा क्षेत्रों से कार्यकर्ता आएंगे। रविशंकर स्टेडियम दुर्ग में भाजपा आमसभा आयोजित करने की तैयारी कर रही है। वहीं, 30 जून को जेपी नड्डा के छत्तीसगढ़ आने की खबर है। वे बिलासपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए बिलासपुर जिला इकाई ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके अलावा वे प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक भी लेंगे। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के गृह जिले में राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह पहला दौरा होगा।

छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश में भी केंद्रीय नेताओं के आने-जाने का सिलसिला बना हुआ है। बताया जा रहा है कि 27 जून को प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से राजधानी भोपाल आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहले धार जाएंगे, फिर भोपाल आएंगे। पीएम भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी जबलपुर-इंदौर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद जनसभा को संबोधित कर राजधानी में रोड शो भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के मध्यप्रदेश दौरे से पहले गृहमंत्री अमित शाह भी एमपी का दौरा करेंगे। अमित शाह 22 जून को मध्यप्रदेश के बालाघाट आएंगे। अमित शाह के बाद 30 जून को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी मध्यप्रदेश आ रहे हैं।

कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की हुई बैठक

रायपुर। कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे की अध्यक्षता में आज कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रास सभाकक्ष में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। इसमे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत अग्रवाल, नगर निगम के आयुक्त श्री मयंक चतुर्वेदी उपस्थित थे। डॉ भुरे ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि शहर के दुर्घटनाजन्य स्थानों को चिन्हित कर दुर्घटना के कारणों पर विचार किया गया है। उन्होंने कहा कि इन स्थानों में अवरोधक और अन्य स्थान जिनके कारण वाहन चालको को वाहन चलाने में परेशानी होती है। उन सभी अवरोधों को हटाया जाए। चौक-चौराहों, अंधे मोड़ अवैध कट जो दुर्घटना के कारण बनते है, उन्हें सुधारा जाए और सड़कों का चौड़ीकरण किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि चिन्हित स्थानों पर आम जनता को सचेत करने के लिए

दुर्घटना जन्य स्थल का बोर्ड और संकेतक भी लगाया जाए।बैठक में पुलिस विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी कि शहर में 24 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए है। जहां पर पिछले कुछ समय से बार बार दुर्घटनाएं हो रही है। एनएच-30 के अंतर्गत अभनपुर में राजलक्ष्मी ढ़ाबा, कमल विहार देवपुरी चौक में बने चैनलाईजर में झाड़ियों का झुड़ है, जिसके कारण वाहन चालको को मोड़ पर देखने की परेशानी होती है। भनपुरी तिराहा में यातायात का काफी दबाव के चलते इंजीनियर सुधार की आवश्यकता है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.